हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार0 ,2 दिसम्बर, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

/1100/02.12.2015**जेके / एजी** /1

प्रश्न संख्या: 2337

अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र कंवर जी।

श्री वीरेन्द्र कंवर: माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें मेरे प्रश्न के भाग-क के सम्बन्ध में जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार दिनांक 10.4.2013 से 31.7.2015 तक कुल 589 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 184 लोगों की मृत्यु हुई तथा 1035 घायल हुए। इसमें मु0 2,53,08,900/- रूपये की अनुग्रह राशि वितरित की गई। इसमें करोड़ों के हिसाब से राशि वितरित हुई है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि ये जो इतनी ज्यादा राशि इन ढाई वर्षों के अन्दर इन सड़कों के ऊपर जो दुर्घटनाएं हुई ,इनमें वितरित की गई, जिसकी हमने यहां पर कल भी चर्चा की थी कि उसके मुख्य कारण कई जगह ब्लैक स्पॉट हैं। तकनीकी खराबी के कारण जो सड़कों को बनाने में कमी रही हैं उसके कारण कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। दूसरे, सम्पर्क मार्गों से तीव्र गति से जो वाहन मेन रोड में एन्टर कर रहे हैं। यह जो लापरवाही है इसको रोकने के लिए क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में यह आश्वासन देंगे कि वहां पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएंगें और वहां पर ज्यादा सांकेतिक बोर्ड भी लगे?

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

02.12.2015/1105/SS-AG/1

प्रश्न संख्या: 2337 **क्रमागत**

श्री वीरेन्द्र कंवर क्रमागत

मैंने जैसे कहा कि ऊना से लेकर लठैनी सड़क तक जहां पर ज्यादा टूरिस्टस जाते हैं और बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं उनके वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए क्या बंगाणा के ट्रेफिक विंग को स्ट्रैंथन करेंगे? मैं यह माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जिला ऊना के अंदर जो सड़कें हैं वे अन्य जिलों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर हैं। मैदानी इलाका भी है और the roads are in a very good condition and many of the roads have just been repaired and re-laid. उसकी

वजह से लोग गाड़ी को काफी तीव्र गति से चलाते हैं। पहाड़ी इलाका होने के बावजूद तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं और बाहर से जो पर्यटक मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं या किसी और काम के लिए आते हैं वे लोग भी अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं तथा कोई रोक नहीं है। इसकी वजह से इस क्षेत्र के अंदर इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं। इसका पूरा ब्योरा दे दिया गया है। जो लोग मरे हैं उनको सरकार ने नियमानुसार पूरा मुआवजा दे दिया है और सब को आबंटित किया गया है। साथ में लोगों को सावधान करने के लिए जहां पर बोर्ड लगने चाहिएं कि यहां तीखा मोड़ है स्पीड की गति को कम किया जाए, वे बोर्ड भी लगाए गए हैं। और भी जहां-जहां आवश्यकता होगी ऐसे बोर्डों को लगाया जायेगा। जहां तक मुआवजे का सवाल है इसके लिए मैनुअल बना हुआ है कि अगर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए यह मुआवजा है और अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसके लिए मुआवजा कुछ और है। नियमानुसार सबको मुआवजा दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र कंवर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सब तो है लेकिन फिर भी इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण क्या है?

02.12.2015/1105/SS-AG/2

दो-तीन कारण जो मेरे ध्यान में थे वे मैंने आपके ध्यान में ला दिए हैं। जैसे वहां पर बाबा बालक नाथ के मेले लगते हैं, बहुत ज्यादा वाहन बाहर से आते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए बंगाणा में जो ट्रेफिक पुलिस है उसको और स्ट्रैंथन किया जाए। सिर्फ एक कर्मचारी से सारा काम नहीं हो पाता इसलिए वहां पर ट्रेफिक पुलिस को स्ट्रैंथन किया जाए और जहां पर बाजार व लिंक रोड हैं वहां पर स्पीड ब्रेकर लगाने से ही गाड़ियों की स्पीड कम होगी। मैं मुख्य मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि यह काम कितने समय के अंदर कर दिया जायेगा। फरवरी-मार्च महीने में फिर से ये मेले शुरू होंगे मेरा आपसे यह निवेदन रहेगा कि उससे पहले यह काम पूरा कर दिया।

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दुर्घटनाएं हुई हैं वे कोई सड़क की खराब कंडीशन की वजह से नहीं हुई हैं। मैं कह रहा हूं कि ऊना की जो सड़कें हैं they are in a very good condition.
जारी श्रीमती के0एस0

02/1110/12.2015.**केएस/एएस**/1

प्रश्न संख्या: 2337 **जारी**--
मुख्य मंत्री जारी----
और इसकी वजह से लोग अपने वाहन बहुत तेज़ी के साथ चलाते हैं, स्पीड-अप करते हैं। खासकर बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, उनको पहाड़ की ड्राईविंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और जब वे स्पीड-अप करते हैं तो due to negligence of drivers दुर्घटनाएं होती है। This is an act of God. उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए। और जहां तक सड़कों का सवाल है वहां पर पूरे साईन लगने चाहिए कि यहां पर चढ़ाई है, यहां पर उतराई है, यहां पर मोड़ हैं इत्यादि-इत्यादि। ये लगाए भी गए हैं और निर्देश भी दिया गया है कि न केवल ऊना में बल्कि हर पहाड़ी क्षेत्रों में इस किस्म के संकेत लगने चाहिए ताकि जो ड्राईवर है उसको मालूम हो कि आगे मोड़ आने वाला है या आगे उतराई या चढ़ाई है। इस तरह के साईन बोर्ड जगह-जगह पर लगने चाहिए और इनको लगाया जाएगा तो ड्राईवर और चौकसी से ड्राईविंग करेगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने मेलों में विशेष प्रबन्ध किए जाने की बात की तो मेलों में तो विशेष प्रबन्ध किया ही जाता है । ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, यात्रियों को गाईड करने के लिए पूरा इंतज़ाम होता है उसके बावजूद भी कई बार एक्सिडैंट्स हो जाते हैं और बंगाणा ट्रैफिक सैल को स्ट्रैंथन करने पर विचार किया जा रहा है । बंगाणा में ट्रैफिक व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने बारे सरकार प्रयत्नशील है।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने वीरेन्द्र कंवर जी के प्रश्न का जवाब दिया, इसमें इन्होंने कहा कि इन सारी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्न पग उठाए जा रहे हैं। मैं ज्यादा तो नहीं पूछना चाहता क्योंकि काफी डिटेल में मुख्य मंत्री जी ने कहा है लेकिन एक ऐसा ही प्रश्न अभी पीछे मॉनसून सत्र के दौरान भी लगा था और लगभग इसी से मिलता-जुलता जवाब

सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का माननीय सदन में आया था। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि लगभग तीन-चार महीने गुज़रने के बाद अभी तक उस पर क्या अमल किया गया? क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सीडैंट्स प्रोन एरिया है तो वह देहरा, मुबारकपुर, चिन्तपूरनी, भरवाईं के बीच का है । वहां पर आए दिन हफ्ते में एक-दो दुर्घटनाएं होती ही है । आपने उस समय भी कहा था जैसे आपने आज कहा कि निम्नलिखित पग उठाए जाएंगें जिसमें आपने कहा कि प्रदेश भर में राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर वाहन दुर्घटनाओं की अधिकता के मध्यनज़र इन को पुलिस पैट्रोलिंग बीटों में बांट कर उच्च मार्ग पुलिस पैट्रोलिंग योजना लागू की गई है ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि ये अभी तक कहां-कहां लगाए गए हैं, ये योजना आपने कहां-कहां पर लागू की?

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ यह भी कहा गया कि व्यावसायिक वाहनों की निगरानी हेतु प्रदेश में व्हिकल ट्रेकिंग सिस्टम प्रस्तावित है जिसके लागू होने पर व्यावसायिक वाहनों की तेज गति व अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अंकुश लगेगा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये कब तक लगा दिए जाएंगें?

अध्यक्ष महोदय, मॉनसून सत्र के दौरान भी इसी तरह का जवाब दिया गया था, मैं जानना चाहता हूं कि इन तीन-चार महीनों के दौरान इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा को बढ़ाना और सड़कें सुरक्षित रहे, ट्रेफिक नियंत्रित रहे, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। वैसे तो सारा हिमाचल ही पहाड़ी है। लाहौल-स्पिति से ले कर किन्नौर तक, सिरमौर से लेकर भरमौर तक सारा इलाका पहाड़ी है । कहीं ज्यादा पहाड़ है तो कहीं पर कम है, कुछ एरिया मैदानी है तो कुछ बिल्कुल पहाड़ी है । Therefore, all the roads in Himachal Pradesh are prone to accidents because of the terrain. और पहाड़ में यह आवश्यक है कि जो भी गाड़ी चलाएं चाहे वह प्रदेश का हो, चाहे बाहर का हो सभी को बहुत ही एहतियात के साथ गाड़ी चलानी चाहिए। उसके लिए जहां पर ज्यादा

02/1110/12.2015.**केएस/एएस**/3

दुर्घटनाएं हो रही हैं, सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

2.12.2015/1115/av/as/1

प्रश्न संख्या : 2337 --------**क्रमागत**

मुख्य मंत्री ------**जारी**

जहां पर ज्यादा ऐक्सिडैंट हो रहे हैं वहां के लिए सरकार ने पुलिस पैट्रोलिंग के आदेश दिए हैं। खासकर ऐसे समय में जब ट्रैफिक ज्यादा हो। मेले हों या कोई स्पैशल ओकेजन हो जिसमें यात्रियों की संख्या ज्यादा आ रही हो। ऐसे समय में उन सड़कों के ऊपर पुलिस पैट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि कोई गाड़ी स्पीड से चल रही हो तो उसको रोका जा सका। इसके साथ-साथ सड़क के किनारे कितने साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो आगे सड़क की हालत बताते हैं कि कहां पर ब्लाइंड मोड़ है। सड़क की कितनी हाइट है; कितनी उतराई है और कितनी चढ़ाई है। ये सारे साइन बोर्ड ड्राइवर को संकेत देते हैं कि आगे सड़क की स्थिति कैसी आने वाली है। ड्राइवर को भी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। अधिकांश ऐक्सिडैंट ड्राइवर की गलती से होते हैं। कई बार स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे सड़कें बढ़ रही हैं और उन पर यातायात बढ़ रहा है उसके अनुसार ट्रैफिक पुलिस की तादाद भी बढ़ाई जायेगी। उनकी चौकियां भी बढ़ाई जायेगी तथा उनकी पैट्रोलिंग भी बढ़ाई जायेगी ताकि वे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में अपना योगदान दे सकें।

समाप्त

2.12.2015/1115/av/as/2

प्रश्न संख्या : 2364

श्री विक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में इस विषय से सम्बंधित प्रश्न हर बार लगाता हूं, कल भी लगाया था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पिछले तीन वर्षों में सूचना एकत्रित नहीं की गई तो विकास कार्य कब होंगे? मेरे विधान सभा क्षेत्र में भूमि स्थानांतरण न होने की वजह से बहुत से विकास कार्य रूके पड़े हैं। वहां पर

एक गवर्नमैंट मिडिल स्कूल गोदरा है। वहां बच्चे पिछले 14 वर्षों से आसमान के तले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, स्वच्छ प्रदेश की बात करते हैं मगर हमारे अधिकतर स्कूलों में शौचालय नहीं है। भूमि उपलब्ध न होने की वजह से वहां पर शौचालय नहीं बन रहे हैं। स्कूल के भवन, पशु औषधालय के भवन और स्वास्थ्य केंद्र के भवन नहीं बन रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि ये कार्य कब तक पूरे होंगे?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने अपनी बात यहां पर रखी है अगर इसी हिसाब से इन्होंने अपना प्रश्न पुट किया होता तो इनको जवाब बड़ी आसानी से मिल जाना था। अपने प्रश्न में इन्होंने पूरे हिमाचल के भवनों और भूमि की बात की है ,इसको इकट्ठा करने में तो निश्चित तौर पर समय लगना है। जहां तक इनके विधान सभा क्षेत्र में किसी प्रकार के भवन हेतु भूमि स्थानांतरण होने की बात है तो ये स्पैसिफिक बता दें। हम विभाग को निर्देश दे देंगे कि उनके लिए लैंड ट्रांसफर कर दी जाए।

श्री विक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि लैंड ट्रांसफर के कई पेपर्ज डी.आर.ओ., डी.सी. ऑफिस में पड़े हुए हैं। मगर वहां पर तैनात कर्मचारी और अधिकारी उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर

2.12.2015/1115/av/as/3

रहे हैं। अतः उनको निर्देश दिए जाएं कि उनके पास जो भी इस तरह के डॉक्युमैंट्स आए हैं उनका जल्दी-से-जल्दी निपटारा किया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ढाई बीघा तक लैंड ट्रांसफर के केस का निपटारा डी.सी. करते हैं तथा पांच बीघा तक डिविजनल कमीशनर करते हैं। उससे ऊपर के केसिज सरकार को आते हैं। आप अपने केसिज के बारे में बता दें, वे जिस भी परिधि में आते होंगे हम विभाग को उस हिसाब से निर्देश दे देंगे।

समाप्त

अगला प्रश्न श्री वर्मा द्वारा जारी

02/12/2015/1120/**टी**0**सी**0/**ए**0**एस**0/1

प्रश्न संख्या: 2513

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन पंचायत के चुनाव से पहले विभाग की ओर से पंचायत रोस्टर को और चुनाव को सुचारू रूप से करवाने के बारे में जो चीजें करनी थी उसके बारे में न केवल प्रदेश की जनता ने बल्कि अब हाइकोर्ट ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। अब मामला हाइकोर्ट में है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा विचित्र सा लगता है कि न जाने विभाग किस परिस्थिति में ये काम कर रहा है। एक ओर से विभाग के मंत्री यह बात करते हैं कि प्रदेश में कुल 3243 पंचायतें हैं और अब नई पंचायतों का गठन किया जाएगा तथा नई पंचायतों के गठन हेतु आवेदन भी मांगे गए हैं। लेकिन बाद में निर्णय होता है कि अभी प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की आवश्यकता नहीं हैं और पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद पंचायत के चुनाव सामने आ गये और यह कहा गया कि प्रदेश में हम पारदर्शिता के आधार पर चुनाव करवाएंगे। इस दृष्टि से प्रदेश में जो 3243 पंचायतें हैं उनमें जो रोस्टर लागू करेंगे उस रोस्टर को लागू करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डवैलप किया है। इस सॉफ्टवेयर से 3243 पंचायतों के लिए रोस्टर जारी होगा कि कौन सी पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी, उसका फार्मूला एक क्लिक से प्रदेश की जनता के सामने आएगा। विभाग की ओर से यह बात बार-बार की जाती है कि हम पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सॉफ्टवेयर बना और फिर सॉफ्टवेयर बनने के बाद निर्णय लिया गया कि सॉफ्टवेयर लागू नहीं किया जाएगा, मैनुअली रोस्टर लागू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये सारी चीजें विरोधाभास के रूप में क्यों खड़ी रही है। अगर सॉफ्टवेयर डवैल्प किया गया था तो उसको लागू करने में क्या दिक्कतें आई ?

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर के मामला हाइकोर्ट में

गया है उसमें क्या-क्या इशुज है जिनका जवाब सरकार को हाईकोट को देना पड़ रहा है।

तीसरा, अध्यक्ष महोदय मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अलग-अलग फार्मूले तय किए गए हैं। अलग-अलग जिले में जिला परिषद के इलैक्शन का रोस्टर कौन तय करेगा, बी0डी0सी0 का कौन तय करेगा और पंचायत का कौन तय करेगा, इसकी सारी डिटेलज यहां पर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद पूरे प्रदेश के अन्दर पंचायत के चुनाव को लेकर एक फार्मूला तय क्यों नहीं किया गया? यह भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :माननीय अध्यक्ष जी जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार ने कभी यह नहीं कहा कि हम नई पंचायत बनाने जा रहे हैं। हमने यह जो कहा है कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार हम नई पंचायते नहीं बनाने जा रहे हैं। जो 3243 पंचायतें थी हम उन्हीं में चुनाव करवाने जा रहे हैं।

दूसरे, माननीय सदस्य ने सॉफ्टवेयर की बात की है। हम जानते हैं कि बदले समय के साथ हमें भी बदलना चाहिए। हमने सॉफ्टवेयर लाँच करने की बात की है और हम चाहते थे कि एक क्लिक पर सॉफ्टवेयर से रिजर्वेशन के बारे में पारदर्शिता लोगों के सामने आए। लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से पूर्व में होता रहा है अभी उसी को चलने दिया जाये। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पूर्व में भी ऐसा होता रहा है कि यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं हुआ तो मैनुअली ही हम उसको करते रहे हैं । आपको मैनुअल रोस्टर को लेकर बहुत सी शंकाएं हैं कि यदि सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोस्टर को न करें तो इसमें गड़बडी की काफी गुजांईश हैं। क्योंकि पूर्व में आपकी सरकार रही है। लेकिन मैं सरकार के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 99.9 परसेंट ऐकूरेसी है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी ---

02.12.2015/1125/NS/AG/1

प्रश्न संख्या: 2513--- **क्रमागत**
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा -------जारी

जबकि हम सरकार के माध्यम से शत-प्रतिशत कहना चाहते हैं कि 99.90 प्रतिशत एकुरेसी इसके अंदर है। हमने डिप्टी कमीशनर को आदेश दिए हैं। यह जो आपके पास हमने उत्तर दिया है इसमें हमने इस बात को ठीक तरीके से कहा है। डिप्टी कमीशनर और पूरा स्टाफ क्योंकि इस पर अलग-अलग जिलों के अंदर अलग-अलग फार्मूला नहीं है। रिज़र्वेशन के लिए अगर आप कहें तो मैं आपको पूरा चार्ट पढ़ कर सुना सकता हूं कि हमारी ग्राम सभा के अंदर सदस्यों की रिज़र्वेशन का क्या मापदंड है? सबसे बड़ी बात यह है कि यह व्यवधान क्यों पैदा हो रहा है? व्यवधान पैदा हुआ जब वर्ष 2010में थ्री-टायर सिस्टम लागू हुआ, उस समय चौथा चुनाव हुआ। उस समय आपकी सरकारी थी। उस समय 50प्रतिशत रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात आई। उसे पहला रोस्टर माना गया। वर्ष 2010पहला रोस्टर हुआ और अब जो हम चुनाव करने जा रहे हैं यह दूसरा रोस्टर है। इस प्रक्रिया को आपके समय भी लागू किया गया था और हमने भी इसी प्रक्रिया को लागू किया है। हाईकोर्ट में लोग तब जाते हैं जब शंकाएं होती हैं। हाईकोर्ट में जाकर लोगों ने इस बात को रखा है कि पहले रिजर्वेशन अनुसूचित जाति की महिलाओं को हो सकती है और अब यह सामान्य जाति की महिलाओं को हो सकती है। जब इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता है तब वे हाईकोर्ट में जाते हैं। अभी पीछे हाईकोर्ट का फैसला आया और उसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजाति और महिला दोनों कैटेगिरी अलग-अलग हैं। इसका फैसला जिला परिषद के हक में आया है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट जब भी इस बात का संज्ञान लेगा तो फैसला सरकार के हक में आएगा।

02.12.2015/1125/NS/AG/2

अध्यक्ष: श्री महेन्द्र सिंह जी ।

श्री महेन्द्र सिंह: आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें कुछ शंकाएं पैदा हो रही हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने पंचायतों

के वार्ड का रोस्टर 2011 की जनगणना के अनुसार दिया है। आपने पंचायतों के प्रधान का रोस्टर, क्योंकि जो वार्ड का रोस्टर है उसके लिए खण्ड विकास अधिकारी को अधिकृत किया है और जो पंचायत के प्रधानों का रोस्टर है उसके लिए जिला पंचायत अधिकारी को अधिकृत किया है। अब दोनों अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। ऐसी बहुत पंचायतें है जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी वार्ड आरक्षित नहीं है। ऐसी पंचायतें जिनमें केवल एक ही परिवार ओ.बी.सी. का है लेकिन जिला पंचायत अधिकारी ने दफ्तर में बैठकर ही पंचायत के प्रधान के पद को एक ही ओ0बी0सी0 के परिवार के लिए आरक्षित कर दिया है। इसको लेकर बहुत लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं। आपने अपने दूसरे उत्तर में एक और बात कही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो रोस्टर है उसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से लिया है। इस विभाग से इस आंकड़े को लेने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी जब आपका खंड विकास अधिकारी हर वार्ड की गिनती करके वर्ष 2011की जनगणना के मुताबिक वार्ड आरक्षित कर रहा है कि उस वार्ड में कितने परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य जाति के हैं। उस आधार पर जब वह उस वार्ड को आरक्षित कर रहा है तो आपने जिला पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को इक्टठा करके इस रोस्टर को क्यों फाईनल नहीं किया? दूसरी बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके गृह जिला मण्डी में दो नगर पंचायतें नई बनी हैं। एक करसोग की नगर पंचायत बनी और दूसरी पधर की नगर पंचायत बनी। तीसरी नगर परिषद नेरचौक की बनी और सरकाघाट नगर पंचायत में भी,

श्री नेगी द्वारा जारी।

02.12.2015/1130/negi/as/1

प्रश्न संख्या: ..2513 **जारी**..

श्री महेन्द्र सिंह ..जारी...

सरकाघाट नगर पंचायत में भी दो वार्ड बरछवाड़ पंचायत की चली गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मण्डी जिला के अन्दर जिला परिषद की 36 सीटें हैं। आपकी एक नगर परिषद बन गई, दो नगर पंचायतें बन गई और एक वार्ड इसमें चली गई । अधिनियम-1994 की धारा 24 कहती है कि आपको एक बराबर की जनसंख्या हर जिला परिषद की वार्ड में रखनी है। एक नगर परिषद और दो नगर पंचायत की जनसंख्या वहां चली गई है उसको ध्यान में रखते हुए क्या आपने मण्डी जिला के सभी

36जिला परिषद की सीटों में बराबर की जनसंख्या के आधार को अपनाया है? अगर नहीं अपनाया है तो आपने जिला मण्डी का रोस्टर कैसे जारी कर दिया कि फ्लॉनी जिला परिषद् की सीट महिला के लिए आरक्षित है, फ्लानी सीट शैडयूल कॉस्ट के लिए आरक्षित है और फ्लॉनी सीट जनरल के लिए आरक्षित है ? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।

दूसरा, आपके विभाग ने जो माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर दिया है, मैं माननीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रश्न को यहां पर लगाया है, वरन् यह कह सकते थे कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए यह प्रश्न नहीं लग सकता है । लेकिन इन्होंने बड़ा दिल रखा है । जो हमारा एडवोकेट जनरल है और जो वकील कोर्ट में उपस्थित होगा वह यहां से निकल करके हमारी जो बात आएगी उसको भी माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में लाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि विभाग और मंत्री जी ने तो पूरे प्रदेश के अन्दर पंचायतों के चुनाव को एक मज़ाक बना करके रख दिया है । आपने न मालूम कितनी घोषणाएं कर दी कि आज ऐसा होगा और कल ऐसा होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ।

02.12.2015/1130/negi/as/2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ओ.बी.सी. की बात कर रहे हैं। अगर यह पंचायत के वार्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें ओ.बी.सी. के लिए कोई रिज़र्वेशन नहीं है । दूसरा, 15 परसेन्ट से ऊपर ओ.बी.सी. के लिए रिज़र्वेशन नहीं है। यह 22 नवम्बर, 2010 को जब आपकी सरकार थी तब का नोटिफिकेशन है कि ओ.बी.सी. के लिए चाहे कांगड़ा हो या कोई अन्य जिला हो, किसी भी ब्लॉक के अन्दर ओ.बी.सी. के लिए 15 परसेन्ट से ऊपर रिज़र्वेशन नही होगी, चाहे पपुलेशन कितनी भी क्यों न हो। शैडयूल कॉस्ट और शैडयल ट्राईब के लिए हमेशा पपुलेशन ही एक क्राइटेरिया है । पंचायत की पपुलेशन के ऊपर ही रिज़र्वेशन शैडयूल कॉस्ट और शैडयूल ट्राईब को दी जाती है। लेकिन ओ.बी.सी. के लिए 15 परसेन्ट रिजर्वेशन है और इससे ऊपर हम उनको रिजर्वेशन नहीं देते हैं। दूसरा, आपने ओ.बी.सी. के अलावा पपुलेशन की बात रखी है। हमारे पास सोशल जस्टिस एण्ड इम्पावरमैन्ट डिपार्टमैन्ट की 2010 की लेटेस्ट जानकारी है और हमने उसके बेस पर यह किया है । उसमें आप कह रहे हैं कि जो 1993 में जनगणना हुई थी और उसके बाद इसमें एडिशन और डिलिशन, ओ.बी.सी. कैटेगरी में कुछ शैडयूल ट्राईब के भी थे

जिनको शैडयूल ट्राईब में दिया गया और कुछ ओ.बी.सी. में ऐड भी किए गए। इसमें एडिशन व डिलिशन सोशल जस्टिस एण्ड इम्पावरमैन्ट डिपार्टमैन्ट के माध्यम से की गई है । यह नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर हमने यह किया है । जो आपने जिला परिषद की बात की है,जो डिलिमिटेशन जिला परिषद के अन्दर हुई है वह शिमला जिला के अन्दर हुई है बाकी जिला के अन्दर मेरे ध्यान में यह लाया गया कि हम जिला परिषद के अन्दर क्यों यह करें कि किसी भाग को इधर डाल दें और किसी भाग को उधर डाल दें और हमने सरकार के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दी थी कि प्रदेश के अन्दर जो भी जिला परिषद हैं उनकी दोबारा से डिलिमिटेशन हम नहीं करेंगे। यह आपने ठीक कहा कि जिला परिषद की आबादी एक बराबर होनी चाहिए। ऐक्ट के अन्दर यह प्रावधान है। जहां तक सम्भव हो सकता है वह भी हमने प्रयास किया है ।

श्री शर्मा जी द्वारा जारी...

02.12.2015/1135/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : ... 2513**जारी**

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री...जारी

जहां संभव हो सकता है वहां हमने प्रयास किया है। आपने ठीक कहा कि जो नगर पंचायतें और नगर परिषदें बनीं हैं ,उनमें पंचायतों का कुछ भाग शामिल किया गया है। उसमें हमने प्रयास किया है, ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुन लीजिए। उसमें जो वांछित जनसंख्या होती हैं वह 1000 से 5000 तक होती है, उसमें कुछ भाग काटकर हमें कुछ पंचायतें 450 या 500 की आबादी की बनानी पड़ीं लेकिन हमने उन पंचायतों में कुछ भाग शामिल करके उनको 500 या 700 की जनसंख्या की पंचायत बनाने का प्रयास किया है।

प्रोO प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'ग' भाग के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि 13वें वित्तायोग के अनुदान को जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में क्रमशः 50:30:20 के अनुपात में बांटा गया है। ये कह रहे हैं कि 14वें वित्तायोग की राशि का आबंटन90 % जनसंख्या के आधार पर और 10% क्षेत्रफल के आधार पर होगा ,अर्थात केवल पंचायतों को ही पैसा मिलेगा। फिर जिला परिषद् और पंचायत समितियां क्या करेंगी? क्या आप इस आबंटन को बदलने का प्रयास करेंगे ताकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भी धन उपलब्ध हो? दूसरे, आपने श्री महेन्द्र सिंह जी के परिपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हमने नोटिफिकेशन जारी कर दी थी।

इन्होंने जो कोट किया था वह एक्ट का पार्ट है। क्या आप एक्ट को नोटिफिकेशन से ओवर रूल कर सकते हैं? क्या स्टेट के पास यह पॉवर है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने इस बात को उठाया है, आपने 13वें और 14वें वित्तायोग की बात यहां पर की। आप जानते हैं कि 13वें वित्तायोग के अंतर्गत जो पैसा आया था वह 538.90 करोड़ रुपया था और जैसे मैंने पहले भी बताया था13 ,वें वित्तायोग ने कहा था कि इसमें से 70% पैसा सीधा पंचायतों को जाना चाहिए। मैंने इस बात को सदन में कहा था कि उस वक्त की सरकार ने इस पैसे का आबंटन 50% जिला परिषदों को30 ,% पंचायत समितियों को और 20% पंचायतों के लिए किया। आप यह कहते थे कि जिला परिषदों के माध्यम से इस पैसे का आबंटन किस प्रकार से किया जा रहा था।

02.12.2015/1135/SLS-AS-2

उसी बात का संज्ञान लेते हुए मैंने इस बात को कहा है कि कम्युनिटी में जैसे देवता के मंदिर के साथ मंदिर की सरायें बनाना ,युवक मंडल बनाना; यह सब भी जिला परिषदों के माध्यम से होता रहा। जिला परिषद के सदस्य महिला मंडल के लिए कहीं 50,000 रुपये की और कहीं 1.00 लाख रुपये की घोषणाएं करते थे जबकि 1.00 लाख या 50,000 रुपये से महिला मंडल नहीं बन सकता। हमने पाया कि बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्ज़ हैं जो नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए यह कहा गया था कि इसमें लगभग 25% ...(व्यवधान)... सर, मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपने जिला परिषदों की बात कही, इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं। जब यह बात हमारे संज्ञान में आई तो हमने जिला परिषदों का पैसा नहीं काटा, उसको 50% ही रखा लेकिन उसमें राइडर लगा दिया कि आप इन-इन कार्यों के लिए पैसा दे सकते हैं। अब केंद्र में आपकी सरकार है।13 वें वित्तायोग के अंदर क्या था ,वह आपके सामने है। अब 14वें वित्तायोग की जो डायरैक्शंज आई हैं ,उसमें हमने अपने जवाब के अंदर कहा है कि 100% पैसा सीधे तौर पर पंचायतों को जाएगा। यह हमारी ओर से नहीं है बल्कि 14वें वित्तायोग की ओर से है। उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि इस पैसे का आबंटन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तभी आज 14वें वित्तायोग ने 100% पैसा सीधे पंचायतों को देने की बात कही है। हमने केंद्र सरकार के सामने यह बात रखी है कि जिला परिषदों को भी पैसा दें। आपने जो कहा, वह ठीक है। हमने सरकार के माध्यम से केंद्र को लिखा है कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए भी पैसा आबंटित होना चाहिए। यह पहल

हमारी सरकार ने की है। लेकिन हमारे पास केंद्र सरकार की ओर से 14वें वित्तायोग की गाईडलाइंज है। उसमें जो हिदायतें हैं, हमें तो अभी उसी के अनुसार चलना है।

अगले वक्ता ..गर्ग जी के पास

02/12/2015/1140/RG/AG/1

प्रश्न सं. 2513-- **क्रमागत**
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के पश्चात

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न श्री महेन्द्र सिंह जी का था कि क्या आप एक नोटिफिकेशन से एक्ट के किसी प्रावधान को ओवर रूल कर सकते हैं, उसका उत्तर नहीं दिया। दूसरे, आप कहें कि 'सरकार आपकी है ,' ठीक है कि दिल्ली में हमारी सरकार है ,लेकिन आपने जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को भी पैसा मिलना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने किस अनुपात में लिखा है कि इस अनुपात में पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि हमने तो अपने तौर पर यहां 50:30 और 20 का रेश्यो किया था। इसलिए आपने भी कोई अनुपात सजेस्ट किया होगा ,तो वह कितना किया है? क्या वह पेपर आप टेबल पर ले करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो अनुपात की हमने कोई बात नहीं की। आपकी सरकार जब पांच साल थी ,तो आपने कौन सा अनुपात भेजा ,जो गाइडलाइन्ज 13वें वित्तायोग की थी ,लेकिन आपने स्टेट में अनुपात चेन्ज कर दिया। हम तो यह कह रहे हैं कि जब 14वें वित्तायोग का सीधा पैसा सौ प्रतिशत पंचायतों को देने की बात कही है ,तो हम उस गाइडलाईन से बाहर नहीं जा रहे हैं। परन्तु हम यह जरूर लिख रहे हैं कि इन चुने हुए प्रतिनिधियों को भी पैसा जरूर मिलना चाहिए। इस तरीके से हमने यह बात की है। रेशो की बात हमने अभी नहीं लिखी है। जहां तक रेशो की बात है, हमने यह जरूर लिखा है कि---

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या आप उस कॉपी को यहां ले करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : जरूर करेंगे। इसके अलावा जो संशोधन की बात है ,हमने अभी रेशो की बात नहीं लिखी है। जो आपने संशोधन की बात कही है, तो

हमने प्रयास जरूर किया है और जो हमारे पास सूचना है उसी के बेसिज पर पॉपुलेशन को एक क्राइटेरिया रखा है।

02/12/2015/1140/RG/AG/2

जो जिला परिषद की आपने बात की, जहां-जहां से कुछ पंचायतें कम हुई हैं ,तो हमने प्रयास किया है कि पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रहे। क्योंकि यदि हम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया और रखते, तो एक जिला परिषद के लिए 25,000 की पॉपुलेशन होती है। हमारी उससे भी ऐक्सीड हो गई थी। लेकिन हम उनको नहीं करते उतने जिला परिषदों को।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि अब यह मामला और भी ज्यादा उलझकर रह गया है और यह आशंका माननीय मंत्री जी के उत्तर से और ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ पूरे प्रदेशभर में कहा गया कि जिला परिषद की डिलिमिटेशन नहीं होगी 11 ,जिलों में नहीं हुई ,लेकिन शिमला जिले में आज नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब यह मामला हाई कोर्ट में चला गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात जिस एक्ट का सन्दर्भ यहां माननीय प्रो. धूमल साहब और श्री महेन्द्र सिंह जी ने भी दिया कि अगर मण्डी जिले में दो नगर पंचायतें और एक नगर परिषद बनी है ,जिला परिषद के 36 वाड्र्ज हैं ,वाड्र्ज कोई कम नहीं हुए, 36 के 36 हैं। लेकिन उसकी पॉपुलेशन तो अलग-अलग है, जो नगर पंचायत या नगर परिषद में चले गए उनका फर्क तो पड़ा। अगर शिमला के लिए आपको डिलिमिटेशन या री-ऑर्गनाईज करने की आवश्यकता पड़ी , तो मण्डी जिले में जिला परिषद की सीटों के डिलिमिटेशन की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस की गई? दूसरी बात मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं, अगर मैं रिजरवेशन रोस्टर से संबंधित बात करूं ,तो शिलाई ब्लॉक में 15 बी.डी.सी. की सीट पड़ती हैं और वहां ओ.बी.सी. के लिए सिर्फ एक सीट महिला की आरक्षित है और वहां ब्लॉक समिति की चेयरपरसन की सीट ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित है। एक सीट पर ही चेयरमैन की सीट आरक्षित कर दी गई है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें पॉलिटिकल स्तर पर मैनिपुलेशन कितनी होती है। मेरा ब्लॉक समिति का होम वार्ड जहां दो बी.डी.सी. की सीटें बनती थीं ,लेकिन इस आशंका के साथ कि वे दोनों भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती है ,उन दो सीटों की एक सीट बना दी गई। ऐसा एक जगह नहीं बहुत जगह हुआ है। इसलिए ये प्रश्न पैदा हुए हैं और किए गए हैं। यह

जो रोस्टर को लेकर यहां बात कही गई ,यह मामला कैबिनेट तक गया कि हम रोस्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू करेंगे ,लेकिन कैबिनेट में इसे रिजैक्ट किया गया और यह इसलिए

02/12/2015/1140/RG/AG/3

रिजैक्ट किया गया कि हमारे लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। क्योंकि मैं ये चीजों को मैनिपुलेट करने की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने 14वें वित्तायोग की बात कही ,तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर 14वे वित्तायोग ने कह दिया कि सारा-का-सारा पैसा ग्राम पंचायत को दें, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो 15-15 पंचायतों से चुने हुए प्रतिनिधि जिला परिषदों के आ रहे हैं ,जो ब्लॉक समिति के मेंबर आए हैं उनके लिए प्रदेश वित्तायोग की ओर से सिफारिश करके उनके लिए विकास के लिए पैसे का प्रावधान करेंगे? क्या इस बात का यहां आप आश्वासन देंगे? इन सारी बातों को लेकर मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारी बातों का जवाब माननीय मंत्री जी यहां दें।

ए.जी. द्वारा अंग्रेजी शुरू

02/12/2015/1145/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 2513**क्रमागत**---

Speaker: I request everybody that don't politicise the issue. This is a very important issue.

श्री सुरेश भारद्वाजः ऐसा लगता है कि आप लोग चुनाव ही नहीं करवाना चाहते हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दल: जब लोगों को आरक्षण का पता लग गया, उसके बाद सॉफ्टवेयर बन्द कर दिया। सॉफ्टवेयर ब्लॉक्स में चला गया है। अब आपका सॉफ्टवेयर कहां है? . . . (Interruption) . . .

Speaker: Why did he say that two BJP panchayats were merged? He said that two panchayats were merged. You should not name any party. This is an important issue. You should not name any party. You said that two BJP panchayats were merged. That could have been said in another sense also. मंत्री जी जवाब दीजिए। . . . (Interruption) . . . You should not name any party here. This is not a question of party. मंत्री जी जवाब दीजिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष जी ,आज इनकी रैली है इसलिए ये लोग जल्दी में हैं और कोई-न-कोई बहाना जाने का ढूंढ रहे हैं। -(व्यवधान)- एक मिनट मेरा जवाब सुन लीजिए। -(व्यवधान) - जो सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है इसको एक्सेल शीट पर बनाया गया है। सॉफ्टवेयर और एक्सेल शीट में जो भी डाटा आप अपलोड करेंगे वहीं रिजल्ट आएगा। यह बात आप स्वयं जानते हैं। -(व्यवधान) - मेरी बात सुन लीजिए। एक्सेल शीट के अंदर जो फॉर्मूला लगाया जाएगा, जो डाटा अपलोड करेंगे -(व्यवधान) -जो आपने बी0डी0सी0 की बात कही- (व्यवधान) -एक मिनट आप लोग मेरी बात तो सुन लीजिए। जो

02/12/2015/1145/MS/AG/2

बी0डी0सी0 की पंचायतों की बात आप कर रहे हैं, इसमें डिप्टी कमिश्नर के पास ऑब्जैक्शन्ज फाइल होते हैं। -(व्यवधान) -मेरी बात सुन लीजिए।

Speaker: Please don't speak when somebody is speaking. Let him speak and then I will give you time.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: यह पारदर्शिता से काम करने की बात है। आप इस बात को छोड़िए। आप इस बात को देखिए कि आप इसमें ऑब्जैक्शन्ज फाइल कर

सकते हैं। आज हाई कोर्ट में लोग गए हैं। जिनको कोई शंका होती है, वे हाई कोर्ट में जाते हैं। हमने प्रयास किए हैं।- (व्यवधान) -

श्री सुरेश भारद्वाज: शिमला जिला का रोस्टर क्यों नहीं निकल रहा है? कब पंचायतों के चुनाव होंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: शिमला का रोस्टर इसलिए नहीं निकला - (व्यवधान) -

श्री रिखी राम कौंडल: मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और मुख्य मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। मुख्य मंत्री जी से बात करके सॉफ्टवेयर का फैसला लेना चाहिए था।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: जो सॉफ्टवेयर की बात आप कर रहे हैं, आज यदि कोई भी ऑब्जैक्शन लगता है तो डिप्टी कमिश्नर ऑनलाइन डाटा दे रहे हैं। हमने उनको ऐसे आदेश दिए हैं। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन डाटा डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से दिया जा रहा है।

Speaker: I think, this Question cannot be solved here. Let the High Court solve it. -(व्यवधान) - मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न में लगभग एक घण्टे का समय लग गया है। -(व्यवधान) -सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप रैलेवेन्ट प्वाइंट पर बात कीजिए। लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। इससे

02/12/2015/1145/MS/AG/3

इश्यू सॉल्व नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न का उत्तर सुनिए। Otherwise the High Court is going to decide this issue.
श्री हंस राज जी बोलिए।

श्री हंस राज: अध्यक्ष महोदय, अति महत्वपूर्ण विषय यहां चर्चा में आया हुआ है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां पर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है और मंत्री जी एक

तरह से शब्दों में सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए था क्योंकि जब सॉफ्टवेयर डवलप हुआ तो उस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए होंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

/ 1150/02.12.2015**जेके/ एएस**/1

प्रश्न संख्या: 2513:---------**जारी**--------

श्री हंस राज:--------**जारी**------

तो उसमें करोड़ों रूपये खर्च हुए होंगे। अगर वह पैसा खर्च हो चुका था तो फिर माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी के बीच में जो कुछ भी हुआ उसका खामियाज़ा पुरी स्टेट को भुगतना पड़ा। यह बात अब माननीय हाई कोर्ट तक पहुंच गई। जितना खर्चा हुआ है क्या उसका विवरण माननीय मंत्री जी इस माननीय सदन में देंगे?

अध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों से अगर लोग एम0एल0ए0 बन कर आए हैं। यहां पर चार-चार माननीय एम0एल0ए0 जिला परिषदों से निकल कर ही बने हैं तो क्या आप ऐसे ही आने वाले जिला परिषदों को साफ करना चाहते हैं। इनकी मंशा क्लीयर है। क्या इस बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बताएंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष जी, हम समझते हैं विपक्ष की नज़र पैनी होनी चाहिए। लेकिन आप इस नज़र से भूलने की कोशिश नहीं करते हैं। हम इसका गिला नहीं करते। लेकिन आपने यहां पर कहा कि सॉफ्टवेयर में हमने खर्चा किया। हमने इस सॉफ्टवेयर बनाने में कोई खर्चा नहीं किया। यह सॉफटवेयर हमने एन0आई0सी0 के माध्यम से डवैल्प किया है और सरकार की तरफ से इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ है, इसलिए यह शंका आपकी गलत है। हमने कोशिश की है,पंचायती राज विभाग ने कोशिश की है, जिलाधीश के माध्यम से यह सारे का सारा मैटर देखा जाता है। इसमें हमने पारदर्शिता लाने की बात की है। मेरे पास पूरे आंकड़ें हैं। यदि हाऊस में चाहिए तो आप डिस्कशन मांगें, मैं पूरे आंकड़ें यहां रखने के लिए तैयार हूं। .....(व्यवधान) .....जय राम जी आपके समय में कोई गलती हुई होगी उसको रैक्टिफाई उन्होंने कर लिया होगा। आप जिस समय मंत्री थे हो सकता है उस वक्त आपके डर से कोई गलती हुई होगी उसको रैक्टिफाई कर लिया होगा। .....(व्यवधान).....

/1150/02.12.2015**एएस/ जेके** /2

अध्यक्ष: श्रीमती सरवीन चौधरी जी ,आप क्या कहना चाहती हैं?

श्रीमती सरवीन चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसमें घपलाबाजी 100 प्रतिशत हुई है। इस बारे में एक उदाहरण मैं देना चाहती हूं कि ओ0बी0सी0 की जो पॉपुलेशन है, वर्ष 1991 का डॉटा आपने लिया है और जनरल कैटेगरी को आपने वर्ष 2011 के हिसाब से लिया है। आपने ओ0बी0सी0 की चिन्ता क्यों नहीं की और इस रोस्टर में आपने उनके साथ घपलेबाजी क्यों की है? वर्ष 1991 और वर्ष 2011 के बारे में आप बताएंगे कि आपने प्रदेश के ओ0बी0सी0 वर्ग के लिए ऐसा क्यों किया है? दूसरे, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगी और एक छोटा सा उदाहरण यहां पर देना चाहूंगी, माननीय मंत्री श्री सुधीर जी यहां पर बैठे हैं। डी-लिमिटेशन में कचलोट पंचायत शाहपुर के साथ जुड़ी। दो बार वह धर्मशाला में थे और सात बार वह शाहपुर में थे और उस पंचायत को आपने इस तरह से तोड़ा है कि उसकी आपने मंहत पंचायत बना दी। जिसकी पॉपुलेशन केवल साढे 400 सौ है। जो सात वॉर्ड उस कचलोट पंचायत के थे उसको सुदेहड़ पंचायत से जोड़ दिया। उस पंचायत की साढे तीन हजार से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। यह सीधा दर्शाता है कि जहां पर कांग्रेस के नुमाईंदें हैं और मंत्री जी ने उनकी बात सुनी। शाहपुर के जो छिट-पुट कांग्रेसी नेता हैं, उनकी बात नहीं आ पाई। आपने इनको तोड़ा है। नई पंचायतें बनाई है। वह पंचायतें भी गलत बनाई हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में रोस्टर में पूरी घपलेबाजी है। यहां पर आप हमें ओ0बी0सी0 के बारे में बताएं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जिस बात का जिक्र कर रही है, मैंने पहले ही कहा कि जो सोशल जस्टिस एण्ड इम्पॉवर का जो हमारे पास आया हुआ है। मैंने इसके बारे में पहले भी कह दिया है। दूसरी, जो आपकी बात कांगड़ा से सम्बन्धित है

/1150/02.12.2015**एएस/ जेके** /3

कोई भी ब्लॉक 15 प्रतिशत से ऊपर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। हमने यहां पर कहा भी कि 15 प्रतिशत से ऊपर हम ओ0बी0सी0 को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। जितने भी कांगड़ा जिला के ब्लॉक हैं वे 15 प्रतिशत से पहले ही ऊपर है। कांगड़ा में कोई

ऐसा ब्लॉक नहीं है जो कि 15 प्रतिशत से नीचे है। इसमें आपको शंका तब होनी चाहिए कि यदि आपकी पॉपुलेशन 80 प्रतिशत बढ़ जाती है। फिर 80 प्रतिशत आपको रिजर्वेशन आपको मिलेगी, वह नहीं है। क्राईटेरिया 15 प्रतिशत तक ही है। यदि आपके यहां पर किसी ब्लॉक में पॉपुलेशन बढ़ भी जाती है तो आपकी सीटें उतनी ही रहेगी। 15 प्रतिशत के ऊपर ही आपको सीटें मिलेगी। कांगड़ा के अन्दर यदि ब्लॉकों में कोई पंचायतें यदि इधर से उधर हो गई है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें ओ0बी0सी0 के साथ कोई परिवर्तन आया हो। --(व्यवधान)--

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

02.12.2015/1155/SS-AS/1

प्रश्न संख्या:2513 **क्रमागत**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री क्रमागत..

नहीं-नहीं, आपको जब मैंने इस बात के बारे में कहा---(व्यवधान)--

श्रीमती सरवीन चौधरी: आपने पीछे से एक बात उठाई है। साढ़े 300 वालों को नयी पंचायत दी है और साढ़े 3000 वालों को एक सिरे कर दिया। कचलोट पंचायत को सुदेहड़ पंचायत से क्यों जोड़ा?

श्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या को कुछ गलती लग रही है। हमने कहा कि हम पंचायतों के लिए 15 परसैंट रिजरवेशन ब्लॉक के ऊपर देंगे इसलिए अगर किसी पंचायत का कुछ पोरशन कट कर उधर चला भी जाए तो ओ0बी0सी0 में कहीं पापुलेशन बढ़ने से 20 या 25 परसैंट हो गई तो भी रिजरवेशन 15 परसैंट ही रहेगी। जब 15 परसैंट से ऊपर है नहीं और ब्लॉक में ओ0बी0सी0 के लिए सिर्फ 2 ही सीटें मिलनी हैं तो सिर्फ दो ही सीटें मिलेंगी चाहे आपकी 80 परसैंट भी पापुलेशन हो जाएं। परन्तु डिपैंट करता है कि आपके पंचायतों में कितने मेम्बर हैं उसके हिसाब से 15 परसैंट से ऊपर है ही नहीं इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आपकी आधी पंचायत उधर चली गई है या इधर चली गई है। --(व्यवधान)---

प्रश्न समाप्त

02.12.2015/1155/SS-AS/2

अध्यक्ष: एक-आध प्रश्न तो और कर लें। श्री सुरेश भारद्वाज जी, आप बोलिये।
श्री सुरेश भारद्वाज**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आजकल सरकार और प्रशासन सी0बी0आई0 और ई0डी0 की रेड के कारण ठप पड़ा हुआ है। क्या यही कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से पंचायत के चुनाव जो समय पर होने चाहिए थे उसका रोस्टर खत्म हो गया। उसका रोस्टर बदल दिया गया और अभी तक शिमला जिला का रोस्टर नहीं बन रहा है। सारे-के-सारे पंचायती राज विभाग में अफरा-तफरी मची हुई है क्या इसके पीछे कारण यही तो नहीं है कि सारी-की-सारी आजकल सरकार कोमा में है और सारा प्रशासन ठप है। इसी कारण चुनाव घोषित नहीं कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, शिमला से निर्वाचित माननीय सदस्य ने जो कहा है यह इनका ख्याली पुलाव है। यह गवर्नमैंट एलर्ट है। आप हमारे केस को सी0बी0आई0 में ले जाईये, ई0डी0 में ले जाओ, यू0एन0ओ0 में ले जाओ, एफ0बी0आई0 के पास ले जाओ या Scotland Yard के पास ले जाओ ,हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। You can't cow down us.

समाप्त

02.12.2015/1155/SS-AS/3

प्रश्न संख्या: 2514
श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करता हूं कि अन्ततोगत्वा 10 लाख रुपये वित्त विभाग ने पुलिस विभाग को स्वीकृत करके दे दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहता हूं कि इस पैसे का पात्र व्यक्तियों को कब तक आबंटन हो जायेगा?

मुख्य मंत्री: मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि कुछ काज़ वितरण की कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी-से-जल्दी यह काम पूरा हो जायेगा।

प्रश्नकाल समाप्त

02.12.2015/1155/SS-AS/4

अध्यक्ष: अब कुछ कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। अब माननीय वन मंत्री जी कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे। ---(व्यवधान)---

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो इनाम दिया गया है, मुख्य मंत्री महोदय, यह कौन-सा इनाम है? स्पष्ट कर दें। ---(व्यवधान)---

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पंचायती राज चुनाव पर प्रश्न पूछा था उसका कोई जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष: एक घंटा तो पूरा हो गया है। यह एक घंटे का प्रश्न हुआ है। ---(व्यवधान)--- प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। ---(व्यवधान)---

(**भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।**)
डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर ही नहीं दिया गया है, हम इसके विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं।

(**भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।**)

मुख्य मंत्री जारी श्रीमती के0एस0

02/1200/12.2015.**केएस/एजी**/1

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हिपोक्रसी की भी एक हद होती है। । एक घण्टे से ज्यादा एक प्रश्न चला उसके बाद महेश्वर सिंह जी का दूसरा प्रश्न था जिसका मैंने उत्तर दिया । पूर्व निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक क्योंकि इनकी पब्लिक मीटिंग हो रही है ये लोग यहां से उठकर भाग गए। This is misuse of the democratic process of this Hon'ble House. Sir, they should be honest to say that 'now we have got a meeting outside and we have to go'. बहाने से उठकर बाहर जा रहे हैं।

अध्यक्ष: माना कि इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था लेकिन प्रश्नकाल को एक घण्टे से ज्यादा समय हम नहीं दे सकते।

02/1200/12.2015.**केएस/एजी**/2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष: अब माननीय उद्योग मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

उद्योग मंत्री (**प्राधिकृत**) :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 20121-3 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं

अध्यक्ष: अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

उद्योग मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 27 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष2011 -1 2(विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-15; और

(iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-1 5(31 मार्च, 201 5तक) ।

02/1200/12.2015.**केएस/एजी**/3

अध्यक्ष: अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

शहरी विकास मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(i) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

02/1200/12.2015.**केएस/एजी**/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष: अब श्री राकेश कालिया, सदस्य , लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16) समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राकेश कालिया :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

(i) समिति का117 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 64वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का118 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 81वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का119 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 83वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा उद्यान विभाग से सम्बन्धित है ।

02/1200/12.2015.**केएस/एजी**/5

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16) का 49वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या 3.12 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल सामान्य उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष: अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2015-16) की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब राम :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2015-16) का21 वां मूल प्रतिवेदन जो कि हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की गतिविधियों

की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2015-16) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 16-2015) के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 13वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

02/1200/12.2015.**केएस/एजी**/6

अध्यक्ष: अब श्री संजय रतन, सदस्य, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16) समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री संजय रतन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16) का15 वां मूल प्रतिवेदन जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

02/1200/12.2015.**केएस/एजी**/7

<u>विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष: अब श्रीमती आशा कुमारी, कार्य-सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) को सभा में उपस्थापित करेंगी तथा प्रस्ताव भी करेगी कि इसे अंगीकार किया जाए ।

श्रीमती आशा कुमारी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सलाहकार समिति के नवम् प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) को सभा में प्रस्तुत करती हूं तथा प्रस्ताव करती हूं कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने नवम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने नवम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि यह माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति द्वारा अपने नवम् प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।
प्रस्ताव स्वीकार।

विधायी कार्य श्रीमती अ0व0 की बारी में----

2.12.2015/1205/av/ag/1

विधायी कार्य :
सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
(प्रस्ताव स्वीकार)
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करेंगे।

2.12.2015/1205/av/ag/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) पुर:स्थापित हुआ।

2.12.2015/1205/av/ag/3

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करता हूं।

2.12.2015/1205/av/ag/4

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) द्वितीय संशोधन विधेयक, 201 5(2015 का विधेयक संख्यांक 22) पुर:स्थापित हुआ।

2.12.2015/1205/av/ag/5

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

आज नियम 324 के अंतर्गत विशेष उल्लेख माननीय विधायक श्री महेन्द्र सिंह जी द्वारा लाए गए हैं परंतु श्री महेन्द्र सिंह जी अनुपस्थित है।

नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा

नियम-63 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी प्रदेश में बढ़ रही पशु तस्करी पर अल्पकालीन चर्चा लाये हैं परंतु वे भी आज अनुपस्थित है।

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

नियम -130 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी प्रस्ताव लाये हैं कि प्रदेश की राजधानी शिमला की वर्तमान यातायात व्यवस्था पर यह सदन विचार करें। मगर श्री सुरेश भारद्वाज जी भी अनुपस्थित है।

2.12.2015/1205/av/ag/6

अब माननीय विधायक श्रीमती आशा कुमारी नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव करेंगी कि "बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।"

इस पर कोई मतदान नहीं होगा और माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री के जवाब के साथ ही चर्चा समाप्त हो जायेगी।

अब माननीय सदस्या श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

पहली बात यह है कि आज विपक्ष के माननीय विधायकों ने जिस तरह से बिना मुद्दे को मुद्दा बनाकर सदन से वाकआऊट किया----------

श्री वर्मा द्वारा जारी

02/12/2015/1210/**टी**0**सी**0/**ए**0**एस**0/1

श्रीमती आशा कुमारी ----- जारी

जिस तरह से विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बिना मुद्दे के मुद्दा बनाकर वॉकआउट किया मुझे इस बात का मुझे अफसोस है। मंहगाई के ऊपर इस मान्य सदन में जो महत्वपूर्ण

चर्चा हो रही है उसमें न हिस्सा लेने के लिए और न ही सुनने के लिए ये यहां पर मौजूद है। मुझे भी इस सदन में 1985 से विधायक रहने का मौका मिला। लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली का हन्न जितना इस बार देखने को मिल रहा है, कभी नहीं मिला। सदन में माननीय सदस्यों का एक हक होता है कि वह प्रदेश के हित की चर्चा सदन में करें। प्रदेश के ज्वलंत मसले सदन में उठाएं। महज झूठी बात को लेकर के रोज सदन से वॉकआउट करना मैं नहीं समझती कि ये कोई स्वस्थ राजनैतिक परम्परा हैं। अध्यक्ष महोदय आज जो विषय सदन में उठाया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय न केवल मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए, मेरे जिले के लिए बल्कि देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई के लिए भारी चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय इसलिए भी है कि लगभग डेढ़ साल पहले ,शायद एक साल सात महीने हो गये हैं, केन्द्र में नई सरकार बनी। केन्द्र में नई सरकार बनने से पहले पूरे राष्ट्र को गुमराह करने के लिए एक पार्टी विशेष ने सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई बनाया तो वह महंगाई का था। जगह-जगह भाषण हुए। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं हरियाणा की प्रभारी भी हूँ और हरियाणा के मामलों को देखती भी हूँ। जहां तक मुझे याद है उस पार्टी के उस व़क्त के डेजिगनेट प्रधान मंत्री ने पहली रैली रेवाड़ी में की थी और रेवाड़ी की रैली में "अच्छे दिन आएंगे" के नारे की शुरूआत हुई। यह नारा महंगाई के साथ जोड़ा गया, युवाओं के साथ जोड़ा गया और जो पैंशनधारी आर्मी परसोनल है उनके साथ जोड़ा गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मुद्दे इस नारे के साथ जोड़कर देश को ठगने का प्रयास किया गया, देश ठगा गया और आज ठगा सा महसूस कर रहा है। अध्यक्ष महोदय मेरे हाथ में आज की तारीख का ट्रिब्यून है, हिन्दुस्तान की लोकसभा में पार्टी लाईन्ज के अक्रॉस संसद में 545 लोकसभा सदस्य हैं और 545 सदस्यों में से 58 सदस्यों ने पिछले कल बढ़ती कीमतों के ऊपर लोकसभा में मसला उठाया। यानि यह मुद्द प्रदेश का ही नहीं बल्कि देशव्यापी

02/12/2015/1210/**टी**0**सी**0/**ए**0**एस**0/2

मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि जो सरकार केन्द्र में आई वह महंगाई को रोकने के वज़ाए महंगाई बढ़ाने का सूत्रपात बन गई। होर्डज़, ब्लैक मार्किटियर्ज जो लोग इन चीजों की समग्लिंग करते हैं, उनकी संरक्षक बन गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है यहां इसी सदन में माननीय बाली जी जवाब दे रहे थे तो चर्चा आई कि अरहर की दाल 95 रूपये किलो हो गई है। माननीय बाली जी ने उस समय भी बहुत अच्छा जवाब दिया। उस समय उन्होंने कहा कि ऐसी सरकारों को देश में राज करने का हक ही नहीं है

जिस सरकार के होते हुए दाल की कीमत 100 रूपये हो जाये। लेकिन अध्यक्ष महोदय आज दाल की कीमत 200 रूपये प्रति किलो है तो केन्द्र सरकार कब इस्तीफा दे रही है? झूठी बातें करके दूसरों के इस्तीफे मांगने वाली देश की सरकार की यह सच्चाई है -

श्रीमती एन0एस0 ---- जारी

02.12.2015/1215/NS/AG/1

श्रीमती आशा कुमारी द्वारा जारी

यह सच्चाई है कि अरहर की दाल 220 रूपये किलो बिक रही है और बेचने वाले कौन हैं? पहले तो छोटे-मोटे दलाल बेचते थे अब तो बड़े दलाल हैं, पतंजलि के दलाल हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग योग सीखाने का काम करते थे वे आज 5000 करोड़ एम्पायर के मालिक हो गए हैं और नूडल्ज और अरहर की दाल बेचते हैं। अरहर की दाल बाज़ार में जब 201 रूपये बिक रही थी तो पतंजलि में 220 रूपए बिक रही थी। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहती हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरे चुनाव क्षेत्र से कुछ लड़कियां मुझसे मिलने आईं थी वे बता रही थी पतजंलि वाले कुछ सौंदर्य प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। मैंने उनको सलाह दी कि अगर सौंदर्य प्रोडक्ट अंजाम वैसा है जैसा इनका मालिक दिख रहा है तो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत करना तो क्या इनकी दालें भी ऐसी हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि हिन्दुस्तान में जो सरकार है वह इन चीजों पर कन्ट्रोल क्यों नहीं कर रही है? जो चने की दाल आज से डेढ़ वर्ष पहले महज़ 35 से 38 रूपये बिक रही थी और श्री बाली जी तो उससे भी सस्ती दे रहे थे। अगर राजा जी और बाली जी तीन दालें हिमाचल प्रदेश में न दें तो प्रदेश की जनता में त्राहि-त्राहि मच जाएगी। आज की तारीख जब किसी गरीब की बेटी की धाम होती है तो उस गरीब को डिपो की दाल नहीं मिलती है। हमारे यहां जो कांगड़ी धाम है उसमें अधिकतर तीन-चार दालें बनती हैं। मैं हाल ही में एक बहुत गरीब परिवार की धाम में गई तो उसने मुझे कहा कि मैंने कोई दाल नहीं बनाई, मैंने अपने खेत से मटर और दूध का पनीर बनाकर के चावल और पनीर की धाम रखी है क्योंकि हम दाल नहीं खरीद सकते। अगर यह हालात हिन्दुस्तान में है और भारत सरकार इस पर नियन्त्रण नहीं कर रही है तो यह सोचने का विषय है। यह अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम असर इस मंहगाई का है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार तीन दालें, तेल, नमक

सब्सिडाईज़ड दे रही है। मगर सब्सिडाईज़ड आईटम थोड़ी मात्रा में मिलते हैं। आज तेल की कीमत क्या है? बाली जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो तेल की कीमत 150 रूपये प्रति लीटर पहुंच गई है। हमारे समय में 85 रूपए पहुंची तो कहते हैं कि महंगाई हो गई है, यह सरकार हट जानी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो केन्द्र में सरकार बैठी है उसे पिछली तारीख से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम डीज़ल और पैट्रोल की बात करें मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार जब केन्द्र में थी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार

02.12.2015/1215/NS/AG/2

में कच्चे तेल का बैरल की कीमत 120 डॉलर से लेकर के 140 डॉलर थी। आज की तारीख में कच्चे तेल की कीमत 40 डॉलर पर आ गई है और बाजार में उसका कोई फर्क नहीं है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जिस दिन कच्चे तेल की कीमत 54 डॉलर से 40 डॉलर पर आई तो भारत सरकार ने तेल की कीमत बढ़ा दी। कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, मगर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ देखें तो हमारे समय में अगर 120 रूपये डॉलर प्रति बैरल था तो आज अगर 40रूपए प्रति डालर रूपये हैं तो इसका मतलब है कि डीजल की कीमत आज देश में 20 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पैट्रोल की कीमत 25 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मगर असलियत क्या है? वास्तव में आज क्या कीमतें हैं? मुश्किल से एक-दो रूपए का फर्क है। जब 120 डॉलर प्रति बैरल था तो इसका मतलब जो मुनाफाखोर है, जो बिचौलिए हैं अदानी, अम्बानी ,कम्पानी, फरमानी हैं जितने भी हैं ,जिनकी कम्पनीज़ हैं इनको फायदा देने के लिए ... (व्यवधान) ..धर्माणी जी तो डिफेन्डर हैं। Defender of faith,इसलिए मैंने फरमानी कहा। अध्यक्ष महोदय यह

श्री नेगी द्वारा जारी।

02.12.2015/1220/negi/ag/1

श्रीमती आशा कुमारी ..जारी...

अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा भारी चिन्ता का विषय है । इसी तरह से मुझे याद है कि हमारी गृहणियों का सबसे बड़ा कंसर्न कुकिंग गैस रहता है। क्रूड ऑयल का रेट घट रहा है लेकिन क्रूड ऑयल बेसड़ जो पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत

हिन्दुस्तान में बढ़ रही है। यह कौन सी इकोनोमिक्स है ? यह इकोनोमिक्स मिस्टर मोदी एण्ड मिस्टर शाह की है । इस इकोनोमिक्स के ऑथर, एग्ज़ीक्यूटर एण्ड बैनीफिशरी यही हैं। अध्यक्ष महोदय, वरन् आप मुझे बताइये कि जब प्राइसिज़ इन्टर-नेशनल मार्केट में गिरेंगी तो क्या देश में उसकी प्राइसिज़ बढ़नी चाहिए? केन्द्रीय पैट्रोलिय मंत्री, मिस्टर प्रधान ने कहा है कि पूरे हिन्दुस्तान में जो कुकिंग गैस की सबसिडी है उसको वह खत्म करने जा रहे हैं। वह एक क्राइटेरिया बनाने जा रहे हैं शायद एक लाख का । वह हिमाचल प्रदेश सरकार से सीखें, यहां पर 35 हजार रूपये तो बी.पी.एल. के लिए है। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और मुख्य मंत्री जी ने यह किया है कि 35 हजार तक जिसकी इन्कम है उनको लो -इन्कम ग्रुप में माना जाता है। आज की तारीख में एक लाख रूपये की वैल्यू ही क्या है ? अगर ऐसा होगा तो सबसिडी पूरे हिन्दुस्तान में बन्द हो जाएगी । अभी श्री धर्माणी जी ने ठीक बताया कि आज शायद 62 रूपये सबसिडाइज्ड वाले कुकिंग गैस का रेट और बढ़ा दिया है। पहले ये नॉन-सबसिडाइज्ड वाले की बात कर रहे थे लेकिन अब सबसिडाइज्ड़ वाले का रेट बढ़ा दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आप मार्किट में सब्जियों के रेट ले लीजिए। मुझे याद है एक बार सरकारें प्याज की कीमत में बनीं और गिर गईं। जसपाल भट्टी जी आजकल नहीं हैं उनका एक्सीडेन्ट में देहान्त हो गया था ,उन्होंने पूरा गले में प्याज़ की माला बना करके कान में फूल जैसे लटका करके बताने की कोशिश की थी कि प्याज़ की कीमत इतनी बढ़ गई । अध्यक्ष महोदय प्याज की कीमतें जितनी इस सरकार के बनने के बाद बढ़ी हैं, मैं नहीं समझती और टाईम यह रिकार्ड है कि एक बार कीमत बढ़ने के बाद, अगर हमारे समय कभी कीमत बढ़ी भी तो कंट्रोल होने के

02.12.2015/1220/negi/ag/2

बाद वापिस 15-16 रूपये पर आ जाती थी । लेकिन अब 40 रूपये से नीचे आने का नाम ही नही है और यह लगातार चली हुई है। मैं एक दिन चण्डीगढ़ में थी वहां पर मैंने पूछा कि मटर का भाव क्या है ? बताया गया कि मटर 155/- रूपये किलो। टमाटर का भाव क्या है? टमाटर 100/- रूपये किलो और तो और कद्दू का भाव भी बढ़ गया है। कौन है जो इसको कर रहा है। अध्यक्ष महोदय अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इनके मंत्री जी का जवाब बता दूं कि उनका हाऊस में क्या था? Mr. Paswan said that the rise in price of pulses was due to several factors such as adverse weather

conditions, rise in transportation (तेल की कीमत घट गई है और पासवान जी की ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ गई है) supply constraints (अब यह आई असलियत) and artificial shortage due to hoarding and black marketeering. अध्यक्ष महोदय, ऑटिफिशियल शार्टेज़ अगर डयू टू होर्डिंग हैं तो उसको कौन देखेगा, कौन रोकेगा और कौन कदम उठाएगा? जो पल्सिज़ हैं, ये हिमाचल प्रदेश तो बाहर से लाता है क्योंकि हमारी इतनी प्रोडक्शन नही है। यह हमारी प्रोडक्शन होती और हम कंट्रोल नहीं करते तब तो मान लिया। यह होर्डिंग सोर्स पर ही हो रही है । यह हो नहीं रही है बल्कि करायी जा रही है ताकि पतांजलि का अरहर की दाल 220/- रूपये किलो बिके। मेरे छोटे भाई ने मुझे ठीक याद दिलाया कि चुनाव के समय एक नारा था कि "हर-हर मोदी और अब नारा है अरहर मोदी "। क्योंकि अरहर की दाल पूरे हिन्दुस्तान में विशेष करके सेन्ट्रल इण्डिया में और साउथ इण्डिया में अरहर की दाल आम फूड है । अध्यक्ष महोदय, बिहार की जनता ने इनको महा-गठबन्धन के ज़रिये दिखा दिया कि अगर ये अपनी ब्लैक मार्केटियर्ज़ को, प्रौटेक्शन की नीति को नहीं बदलेंगे अगर ये ....

श्री शर्मा जी द्वारा जारी...

02.12.2015/1225/SLS-AS-1

श्रीमती आशा कुमारी ...जारी

कि अगर ये अपने ब्लैक मार्किटियर्ज़ के लिए प्रोटैक्शन की नीति को नहीं बदलेंगे ,अगर ये पातंजलि जैसे आऊटफिट को, मैं उसे आऊटफिट ही कहूंगी, वह अपने आपको इंडस्ट्रियलिस्ट कह सकते हैं ,अगर पातंजलि जैसे आऊटफिट के ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे तो अध्यक्ष महोदय, वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की जनता इनको निकट भविष्य में यही आईना दिखाएगी। पांच साल बीतते बहुत समय नहीं लगता है।

अध्यक्ष महोदय ,बिहार में तो गठबंधन की बात थी, मगर मध्य प्रदेश, जो अरहर की दाल पैदा करने वाला एक सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे राकेश कालिया जी वहां के प्रभारी-सचिव भी हैं। वहां पर लोकसभा की सीट का चुनाव हुआ और मैं आपके माध्यम से इनको बधाई देना चाहूंगी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो विजय हुई, वह इन्हीं

नीतियों के कारण हुई है। डेढ़ साल में अगर किसी सरकार की महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर साख गिरी है तो वह यही केंद्र सरकार है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं अपनी चर्चा खत्म करने से पहले ज़रूर कहना चाहूंगी। मैं भी कह रही हूं कि केंद्र सरकार ने महंगाई के मुत्तलिक या कीमतों को कम करने को लेकर कुछ नहीं किया। एक काम ज़रूर किया जो हम और आप कोई नहीं कर पाया और न हमारी केंद्र की उस समय की सरकार कर पाई। इन्होंने दालों को ड्राई फ्रूट बना दिया क्योंकि दालों की कीमतें ड्राई फ्रूट जैसी हो गई है। इस उपलब्धि का श्रेय हम इनको ज़रूर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हिमाचल सरकार को बधाई देना चाहूंगी और निवेदन करना चाहूंगी कि जो राहत सब्सिडाईज्ड फूडग्रेन के माध्यम से दी जा रही है, आप इसको जारी रखें। इसके अलावा जो छोटे स्तर के होर्डर्ज़ एंड ब्लैक मार्किटियर्ज़ हैं, जिन्होंने वैजिटेबल या फ्रूट्स को लेकर होर्डिंग एंड ब्लैक मार्किटिंग का काम शुरू कर रखा है ,उनके ऊपर भी आप कुछ सख्त कदम उठाएं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के प्रधान मंत्री और कंज्यूमर्ज़ अफेयर्ज़ मंत्री को आप ज़रूर एक पत्र लिखेंगे और जो महंगाई को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का कंसर्न है, वह बात आप उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

02.12.2015/1225/SLS-AS-2

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार जी चर्चा में भाग लेते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव श्रीमती आशा कुमारी जी, माननीय सदस्य एंड सैक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यहां पर रखा है। बढ़ती हुई महंगाई आजकल की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। माननीय श्रीमती आशा कुमारी जी ने विरोधी पक्ष के बैंचिज की बात की कि इस मामले को लेकर वह बाहर निकले।

)श्रीमती आशा कुमारी, सभापति के रूप में पदासीन हुई।)

वह मामला तो समाप्त हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आपने अगला प्रश्न भी कॉल कर दिया था और उसका जवाब भी मिल गया था। लेकिन उनकी मंशा गलत थी।

उनकी पहले से ही मंशा थी कि उनके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। यह इनकी दोगली नीति है। इसलिए इन्होंने इस इसु की बात की। इन्होंने बाहर रैली में जाना था और रैली में जाने के लिए ये बहाना ढूंढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा दोगली नीति रही है। आज की इस बात से भी यह स्पष्ट होता है कि उनके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। लोकसभा के चुनाव हुए लगभग 18 महीने हो गए। इन चुनावों से लगभग एक-डेढ़ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर सभा में जाकर ,जहां भी इनकी सभा होती थी,

जारी ..गर्ग जी

02/12/2015/1230/RG/AS/1

श्री कुलदीप कुमार----क्रमागत

जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हर सभा में जाकर इन्होंने जहां-जहां भी सभा होती थी ,वहां जाकर महंगाई के खिलाफ मुद्दे बनाए, जबकि उस समय कोई महंगाई नहीं थी ,लेकिन इन्होंने हर जगह जाकर यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बनाया और जनता को एक प्रलोभन दिया कि हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे और जनता से वायदे किए कि हम महंगाई को नीचे लाएंगे। इसके साथ-साथ इनके जो, मैं तो आर.एस.एस. के विंग कहूंगा ,भारतीय जनता पार्टी का विंग कहूंगा ,उन्होंने मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि कोई गाने वाले उस समय चले थे, कोई बाबे चले थे और कोई योगा बाबा चले थे, कभी टी.वी. के ऊपर एक गाना आता था कि 'महंगाई डाइन मार जात है' और इसे हर ख़बर के पश्चात लगा देते थे कि 'महंगाई डाईन मार जात है।' इन्होंने इस प्रकार से अपनी पब्लिसिटी की।

सभापति महोदया, जैसा श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा, एक योग बाबा निकला और योग बाबे ने योग सिखाते-सिखाते ,वह योगा कम सिखाता था बल्कि यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ ,डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ उसने जनता में ज़हर घोला। चाहे वह कालेधन की बात हो, चाहें महंगाई की बात हो और उस समय इन्होंने जनता के साथ ऐसे-ऐसे वायदे किए। इन्होंने जनता के साथ एक तो महंगाई को कंट्रोल करने का वायदा किया कि हम महंगाई को नीचे लाएंगे और गरीबों को राहत दिलाएंगे। दूसरा, इन्होंने जनता से और कितने वायदे किए और आखिर में जब इनकी बात नहीं बनी, तो इन्होंने कहा कि हम सौ दिन के अंदर-अंदर कालेधन को विदेशों से

वापस लाएंगे और पता नहीं कि कितने करोड़ों-अरबों की फिगर ये देते थे चाहे वह योगा बाबा था ,चाहे वे आज के जो प्रधानमंत्री हैं ,कहते थे कि यदि हम सौ दिन के अंदर कालाधन विदेशों से वापस नहीं लाए, तो हमें फांसी चढ़ा देना। ये कहते थे कि कालाधन विदेशों से वापस लाकर हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपये जाएगा। गरीब को क्या चाहिए था। गरीब को चाहिए था कि 15 लाख रुपये मिलेंगे और यदि ये सरकार सत्ता में आएगी, तो हमारी दरिद्रता भी दूर होगी। इसलिए गरीबों ने इनको डटकर वोट दिए। वे इनकी ठगी में आ गए। इन्होंने पूरे भारतवर्ष में उनको वोटों के द्वारा ठगा है। इतनी इनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा सीटें इनको आएंगी ,लेकिन इनकी सीटें आईं और इनकी सरकार केन्द्र में बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद अब इनको 18 महीने होने जा रहे हैं,

02/12/2015/1230/RG/AS/2

इनके जो वायदे थे ये उन वायदों को भूल गए और न कालाधन विदेशों से आया और न ही महंगाई कंट्रोल हुई।

सभापति महोदय, यहां तक की जो गरीब है, गरीब इस महंगाई में परास्त होता जा रहा है और पूरे भारत में गरीब का जीना दूभर हो गया है। आज दाल भी 200/-रुपये किलो हो गई है। जो सब्जियां नहीं ले सकते थे, कोई और चीज नहीं ले सकते थे और गरीब के घर में अपने परिवार को चलाने के लिए सिर्फ एक दाल का सहारा होता था , वह रोज दाल बनाकर अपने परिवार को चलाया करता था ,लेकिन आज कई दालें भी 200/-रुपये किलो से अधिक हो गई हैं। यह जो महंगाई बढ़ी है चाहे वह सब्जियों की बात हो, चाहे टमाटर की बात हो या अन्य खाद्य पदार्थों की बात हो ,आज महंगाई आसमान को छू रही है। आज गरीब का जीना दूभर हो गया है। लेकिन आज केन्द्र में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बजाय वे महंगाई को कंट्रोल करते ,वे दूसरी चीजों में भाषणबाजी, बहानेबाजी में अपना समय पास कर रहे हैं और गरीब का जीना दूभर हो रहा है। सिर्फ 18 महीनों में किसकी कमाई हुई, किसकी तरक्की हुई है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के। जो इनके बड़े-बड़े होर्डर्ज हैं ,बड़े-बड़े स्टॉकिस्ट्ज हैं उनकी वजह से यह महंगाई हुई है। या फिर जो बड़े-बड़े अरबपति हैं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

02/12/2015/1235/MS/AG/1

श्री कुलदीप कुमार जारी-------

ये जो बड़े-बड़े अरबोंपति लोग अदानी और अम्बानी हैं इनकी कई-कई करोड़ रुपये आमदनी इन 18 महीनों में बढ़ी है। खासकर यदि बाबा रामदेव की आमदनी का पिछले 18 महीनों का हिसाब लगाया जाए तो वह करोड़ों रुपये बढ़ी है। इन्होंने जनता से जो भी वायदे किए थे उनमें से आज तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इन 18 महीनों में जनता को इनका पता चल गया है। जब हम बोलते थे तो लोग सोचते थे कि ये कांग्रेसी हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हम कहते थे कि बी0जे0पी0 बहुत ही झूठी पार्टी है लेकिन अब यह साफ हो गया है और इनका दोगला चेहरा सारी जनता के सामने आ गया है कि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने जनता से किए हुए किसी भी वायदे को अभी तक पूरा नहीं किया है। जब यू0पी0ए0 की सरकार थी उस वक्त एक बार प्याज कुछ महंगा हो गया था। इन्होंने महंगाई के लिए बहुत हो-हल्ला किया। आपको याद होगा कि इनकी नेत्रियां श्रीमती सुषमा स्वराज, हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी ने अपने गले में प्याज के हार डालकर डांस करने शुरू कर दिए थे। आज इनको महंगाई नज़र नहीं आ रही है? आज सब बुत बनकर चुप बैठे हैं और जनता को धोखे में रखकर अपने काले कारनामों पर परदा डाल रहे हैं। आज जितनी महंगाई बढ़ी है उसको देखकर मैं माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करता हूं और इनको गरीबों की आसीस लग रही है क्योंकि पिछली बार जब हमारी कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी उस वक्त सस्ते राशन की जो पॉलिसी चलाई गई थी, वह आज तक चल रही है और हिमाचल की जनता को राहत मिली है। अभी कुछ समय पहले हमारी शिमला में रैली हुई तो वहां भी एक नाटकबाज कह रहे थे कि दूसरी जगह दाल की बजाए मुर्गा खा रहे हैं। क्योंकि मुर्गा सस्ता है और दाल महंगी है। लेकिन माननीय बाली जी ने कहा कि हमारे हिमाचल प्रदेश में दाल अभी भी मुर्गे से सस्ती है और जनता सस्ती दालें और सस्ता अनाज यहां ले रही है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री और हिमाचल सरकार का पुनः धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारे पिछले टैन्योर में यह नीति

02/12/2015/1235/MS/AG/2

चलाई गई थी। उसके बाद पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इनके गले ये स्कीम पड़ गई। इन्होंने इस स्कीम को बन्द करने की कोशिश की क्योंकि इनसे यह नहीं चल पा रही थी। लेकिन ये इसे बन्द नहीं कर पाए। अगर ये इसे बन्द कर देते तो इनका मलियामेट हो जाता। यही हाल इनका अब बिहार में हुआ है। इन्होंने बिहार और पूरे देश में जो वायदे किए थे ,इन 18 महीनों में उससे उलट हुआ है। जो महंगाई कन्ट्रोल करने की बात हुई थी, महंगाई घटी नहीं बल्कि बढ़ गई। यानी न बाहर से कोई काला धन आया और न महंगाई कन्ट्रोल हुई। उसका परिणाम बिहार की जनता ने इनको दे दिया है। बिहार की जनता ने इनको बता दिया है कि आपका जो 18 महीनों का कार्यकाल है वह क्या है।

इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बाई-इलैक्शन में जीत हुई है। हालांकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन उसके बावजूद बाई-इलैक्शन कांग्रेस जीती। अब धीरे-धीरे पूरे हिन्दुस्तान की जनता इनके दोगले चेहरे को समझ चुकी है कि ये बोलते कुछ हैं और जनता को ठगने की बात करते हैं।

मैं प्रधान मंत्री जी का इस देश के प्रधान मंत्री होने के नाते बहुत आदर करता हूं। वे हमारे हिन्दुस्तान के माननीय प्रधान मंत्री हैं। वे बातें बहुत अच्छी-अच्छी और बढ़िया-बढ़िया करते हैं। लच्छेदार बातें करते हैं लेकिन अगर उन भाषणों को प्रैक्टिकली जनता के बीच में लागू नहीं करेंगे,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

/1240/02.12.2015**जेके /एजी** 1 /

श्री कुलदीप कुमार:-----**जारी**-----

ये लच्छेदार बातें करते हैं। अगर आप उन बातों को प्रैक्टिकली जनता के बीच में लागू नहीं करेंगे, तबदील नहीं करेंगे और उन नीतियों को नहीं बनाएंगे तो बिहार जैसा हाल आने वाले भविष्य में होगा। जनता मंहगाई से और इनकी नीतियों से त्रस्त है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का जो कार्यकाल रहा है उसके अन्दर बेहद विकास हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बड़ा तेज़ी से विकास हुआ है। चाहे स्कूलों की बात हो, सस्ते राशन की बात हो और चाहे सड़कों की बात हो इनमें बेहद विकास हुआ है। ये अब यह भी सोचने लगे हैं कि कहीं बिहार जैसा हाल हिमाचल प्रदेश में न हो। कहीं एम0पी0 जैसा

हाल हिमाचल प्रदेश में न हो। इसलिए अब ये रैलियां आदि करके अपने सरवाईवल की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदया, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय-हिन्द।

समाप्त

/1240/02.12.2015**जेके /एजी**2 /

सभापति: अब माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह: सभापति महोदया, आज जो इस माननीय सदन में नितान्त सामयिक और गरीबों से जुड़े हुए विषय के सन्दर्भ में आपने इस माननीय सदन के सदस्य होते हुए चर्चा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस तरह से आपने गरीबों से जुड़ा हुआ विषय यहां पर रखा और बड़े विस्तार से सभी बिन्दुओं पर चर्चा की ,उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। महोदया, बार-बार कहा जाता है कि प्रजातंत्र की इस गाड़ी के दो आवश्यक पहिये हैं। खेद का विषय यह है कि एक पहिया तो यहां पर है दूसरा न जाने कहां लुढ़क गया। अच्छा होता यदि ये यहां पर केन्द्र से संबंधित विषय ज्यादा लाते और यहां पर उपस्थित होते और इस प्रस्ताव पर हम उनके विचार जान पाते। महोदया, बड़ी तीव्रता से मंहगाई बढ़ी है और आवश्यक वस्तुओं के दाम आज आसमान को छू रहे हैं। लोग कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे परन्तु आज कुम्भकर्ण की नींद में सो कर उन अच्छे दिनों के स्वप्न ले रहे हैं। दाल, सब्जी क्या, आज हरेक चीज़ मंहगी है और निरंतर मंहगी होती जा रही है। आरम्भ में जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो इन्टर नेशनल मार्किट में क्रूड ऑयल की कीमत थोड़ी घटी और तुरन्त केन्द्र में सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा कि धन-धन मोदी। इनके आते ही पैट्रोल और डीज़ल सस्ता हो गया। उन्होंने कहा कि अब अच्छे दिनों की शुरूआत है। आपने यहां पर जो आंकड़ें प्रस्तुत किए कि आज क्रूड ऑयल की कीमत इन्टर नेशनल मार्किट में तीन गुणा घट गई तो एक मूल प्रश्न है कि आज यह केन्द्र सरकार कुम्भकर्ण की नींद से उठ कर पैट्रोल और डीज़ल तीन गुणा सस्ता क्यों नहीं करते है? दालों की कीमत का भी आपने यहां पर सारा वर्णन किया है। अरहर की दाल गरीबों की दाल कहलाई जाती है। इस दाल को कभी भी ब्याह-शादी में हमारे यहां लोग नहीं बनाते है, क्योंकि इसको सस्ती दाल माना जाता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

02.12.2015/1245/SS-AG/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागत

राजमाह ,माश और चने की दाल का अपर हिल्ज़ और सारे मंडी में प्रचलन है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए कि आपने स्वयं कहा कि अरहर दाल पकाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं हैं इसलिए सब्जियां पका रहे हैं। कब यह केन्द्रीय सरकार कुम्भकर्ण की नींद से उठेगी, पता नहीं। क्योंकि इनकी हालत ऐसी है, कहते हैं कि जब कुम्भकर्ण सोता था तो छः महीने तक नहीं उठता था और उसको जगाना पड़े तो ढोल-नगाड़े बजाने पड़ते थे तब नींद खुलती थी। एक दफा जब वह जागा तो एक हजाम को बुलाया गया और वह दाड़ी बना रहा था। कुम्भकर्ण को नींद आई, उसने जम्हाई के लिए मुंह खोला तो उस्तरा अंदर चला गया। आगे उस्तरा और पीछे हजाम भी अंदर चला गया। उसको उस्तरा तो नहीं मिला लेकिन उस पेट में एक आदमी डंडा लेकर घूमता हुआ मिला। उसने पूछा कि भईया क्या ढूंढ रहे हो तो उसने कहा कि मेरा उस्तरा निगल गया और मुंह बंद कर दिया। अब मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। उसने कहा, अरे यार, तेरा उस्तरा कहां मिलेगा यह छः महीने पहले मेरी भैंस निगल गया था वह मुझे इसके पेट में नहीं मिल रही है। ऐसी नींद में सोई हुई सरकार है। इसको भी उसी प्रकार ढोल-नगाड़े बजाकर जगाना पड़ेगा। मैंने आरम्भ में कहा कि यह विषय केन्द्र की सरकार से जुड़ा हुआ है लेकिन जहां तक हिमाचल सरकार का संबंध है उसको महंगाई को रोकने के लिए इसमें अपना योगदान करना चाहिए। जो लोग होर्डिंग करते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हर वस्तु का एक मार्जन और प्रॉफिट होता है वह फिक्स करना चाहिए ताकि इस आड़ में यहां कोई ज़रूरत से ज्यादा अधिक महंगी चीज़ न बेच सके चाहे वह दाल है या सब्जी है। जहां तक किसानों का संबंध है आज भी इस महंगाई के समय में जब वह अपनी उपज लेकर सब्जी मंडी में बेचने जाता है तो जिस टमाटर और प्याज की बात महोदया कर रही थीं वह किस भाव बिकता है? यहां पर स्वयं कृषि मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर वहां पर 30 रुपये बिकता है तो बाहर 150 रुपये बिकता है तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उस मार्जन और प्रॉफिट को कौन तय करेगा और किसान को उचित लागत मूल्य कौन दिलायेगा? निश्चित रूप से किसान की इस उपज का

02.12.2015/1245/SS-AG/2

लागत मूल्य उसको कम-से-कम तो मिले यह हिमाचल सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। कहां मटर चंडीगढ़ में 150 रुपये किलो बिकता है और कहां यहां पर बड़ी मुश्किल से 100 रुपये तक पहुंचेगा और लाहौल-स्पिति में बैठे हुए किसान को 40 रुपये किलो से ऊपर नहीं मिलेगा। मंत्री महोदय, सब्जी मंडी आपके अधीन है इसलिए जो उनको मूल्य मिलना चाहिए वह कम-से-कम लागत मूल्य तो मिलना चाहिए। अगर सम्भव हो तो फिर लाभकारी मूल्य भी आप फिक्स करें ताकि वह भी कुछ-न-कुछ कमा सके। यह नितांत आवश्यक है। महोदया, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन और माननीय सदस्य भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेंगे इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति: धन्यवाद। अब माननीय सदस्य, श्री जगजीवन पाल जी (मुख्य संसदीय सचिव) चर्चा में भाग लेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

02/1250/12.2015.**केएस/एजी**/1

श्री जगजीवन पाल: आदरणीय सभापति महोदया, नियम 130 के अंतर्गत जो चर्चा आपने उठाई है, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा प्रदेश ओर देश की जनता के लिए है। हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। जो इस वक्त हालात बने हैं, चाहे दिल्ली की एन.डी.ए. की सरकार हो चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, बड़ा अच्छा होता यदि आज इस गम्भीर चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी हिस्सा लेते और जो यह गम्भीर समस्या है, इसके ऊपर एक अच्छा सा प्रस्ताव डालकर दिल्ली की सरकार को जगाने की कोशिश करते लेकिन अफसोस कि ये लोग हिमाचल की जनता को मंहगाई के मुद्दे से भटका रहे हैं और रैलियां कर इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जब डेढ़ वर्ष पहले चुनाव हुआ था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर कहते थे कि यू0पी0ए0 सरकार की वजह से भारतवर्ष में मंहगाई है और उस वक्त मेरे ख्याल में अरहर की दाल 85 रु0 किलो थी। प्याज के दाम थोड़े बढ़े थे। आदरणीय कुलदीप कुमार जी ने ठीक

कहा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा था, उनकी नेत्रियों ने प्याज के हार गले में डालकर दिल्ली में संसद के सामने प्रदर्शन किया था लेकिन आज देश के सामने क्या हालात है? आज दालों की कीमतें जिस तेजी से बढ़ीं हैं, दालों की ही नहीं बल्कि सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी हैं लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड दालों ने तोड़ा है और जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो उस वक्त केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय जेटली जी रोज़ शाम को एक प्रैस कॉंफ्रैंस करते थे और कहते थे कि काला बाज़ारी की इतने हज़ार टन दालें पकड़ी गई है और जैसे ही वह चुनाव खत्म हुआ कीमतों में कोई कमी नहीं आई और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो होर्डिंग करने वाले लोग हैं, वे सभी भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित दलाल है। जब चुनाव चल रहे थे उन लोगों को पूरे देश की जनता ने देखा है । चाहे वह देश के चुनाव थे या बिहार के चुनाव थे । आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जो इस वक्त देश के प्रधान मंत्री हैं, वे कैसे पूरे हिन्दुस्तान में हवाई जहाज में सफर करते थे और चुनाव के समय जो अरबों रुपया इनकी पार्टी ने इकट्ठा किया था, वह कहां से आया? वह इन्हीं दलालों से आया था और उनको भारतीय जनता

02/1250/12.2015.**केएस/एजी**/2

पार्टी की सरकार अब मौका दे रही है कि आप जनता को जितना लूटना चाहते हो लूट लो और हमारे लिए जो खजाने आपने खाली किए हैं, इलैक्शन लड़ने के लिए हमें जो फंड दिया है उसको पूरा करो। उनको खुली छूट दे रखी है। बिहार का चुनाव हारने के बाद अब वह छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं?अब उन काला-बाजारी करने वाले चोरों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? यह ठीक है कि इस वक्त सारे देश की जनता और हमारे प्रदेश की जनता भी गुमराह हुई है । प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एक नारा दिया गया, वे बड़ी-बड़ी रैलियों में आते थे

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

2.12.2015/1255/av/as/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) ------जारी

बड़ी भारी रैलीज में आते थे और कहते थे 'अच्छे दिन' ,अब वह जुमला बन गया है। अब वह अच्छे दिन चले गये। लोग यू.पी.ए. सरकार को फिर से याद करने लगे हैं। यहां पर

बैठे सभी आदरणीय सदस्य जानते हैं कि श्री अरुण शोरी जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 'थिंक टैंक' थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। उनका बयान आया कि अब देश के लोगों ने पूर्व प्रधान मंत्री डॉ.मनमोहन सिंह जी को याद करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक और कानून-व्यवस्था के हिसाब से देश का प्रबंधन ठीक चला हुआ था। कहा गया कि काला धन आयेगा और हर भारतीय चाहे अमीर है या गरीब है; सभी को 15-15 लाख रुपये की राशि दी जायेगी। हम लोग भी उस समय जब जनता के बीच जाते थे तो भाषण में कहते थे कि कांग्रेस पार्टी की मदद करो। यह बात चुनाव के दौरान हमारे खिलाफ भी गई। हम भी उस समय यही सोचते थे कि अगर वास्तव में ही 15-15 लाख रुपये की राशि आ गई तो हम क्या करेंगे। मगर अब देश की जनता प्रधान मंत्री जी से सवाल कर रही है। अगर इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से पूछा जाए तो वह कहते हैं कि यह तो एक चुनावी जुमला था। अगर वह 15-15 लाख रुपये की राशि आ जाती तो आज शायद भारत की जनता इस बढ़ती महंगाई का सामना कर सकती थी। वह पैसा भी नहीं आया और न ही कोई अच्छे दिन आए। केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय क्रूड ऑयल के रेट कम हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके भाव गिरे तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं भाग्यवान प्रधान मंत्री हूं। मेरे आने की वजह से तेल के भाव कम हो गये। उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ गये। जब दिल्ली का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हमारे भाग्य वाले प्रधान मंत्री जी आए हैं। ठीक है, दिल्ली के चुनाव में हमारी पार्टी के ज्यादा लोग नहीं जीते। वहां केजरीवाल के नेतृत्व में 'आप' पार्टी की सरकार बनी। अगर प्रधान मंत्री जी भाग्य वाले हैं तो दिल्ली में भी भाग्य वाले लोगों को लाना चाहिए

2.12.2015/1255/av/as/2

था मगर दिल्ली की जनता ने इनके लोगों को नकार दिया। बिहार में भी नकार दिया। बिहार में एक महागठबंधन हुआ और उनकी जीत भी हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बनी। यह भी एक पहलू है कि आज तक केंद्र में जितनी भी सरकारें बनीं, उनमें जितनी गिरावट और देश की जनता का मोह भंग प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुआ है उतना जल्दी पहले कभी नहीं हुआ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी हारी है। वहां पर प्रधान मंत्री जी ने कितनी ही सभाएं की और अपने भाषण में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उसको बिहार की

जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। बिहार में जो मेनडेट आया है वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया है। देश की जनता जो महंगाई की मार झेल रही है उसकी पूरी जिम्मेवारी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। इस समय पूरे देश और प्रदेश में महंगाई की वजह से त्राहि-त्राहि है।

माननीय सभापति जी, आपने इस माननीय सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी को बधाई भी देता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी राहत है। वर्ष 2003 से 2007 तक मुझे भी इस माननीय सदन का सदस्य रहने का मौका मिला था। मैं उस समय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन था। वर्ष 2006-07 के दौरान एक बहुत बढ़िया स्कीम .....

श्री वर्मा द्वारा जारी

02/12/2015/1300/**टी0सी0/ए0एस0**/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगजीवन पाल) ----- जारी

वर्ष 2006-07 के दौरान एक बहुत बढ़िया स्कीम सभी लोगों को, ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 के लोगों को भी, हर चीज से ऊपर उठकर जिसका भी राशन कार्ड में नाम था उनके लिए यह योजना शुरू की गई। इसमें तीन दालें, नमक और सरसों का तेल देने का निर्णय लिया गया और इस योजना को शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान का पहला प्रदेश था। आज भी प्रदेश में राशनकार्डधारी हर वर्ग के लिए लोगों के लिए दालें 40 रूपयें तक मिल रही है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ कि इस योजना को आगे भी चालू रखा जाए ताकि प्रदेश के लोगों को महंगाई की मार से बचाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायती राज का रोस्टर ठीक प्रकार से लागू नहीं हुआ का बहाना बनाकर सदन से बाहर निकल गये। आज इस चर्चा में हिस्सा लेते तो बहुत अच्छा होता। एक और बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वैसे तो चुनाव के दौरान बहुत से बाबे और बाबियां आते हैं लेकिन 1992में एक बाबा रामदेव भी आए। पहले तो लोग यह समझे कि

यह कोई योग सीखाने वाले बाबा है और इनका जब भी कोई योगा का कैंप होता था तो उसमें सब लोग जाते थे। लेकिन जब एक साल लोकसभा के चुनाव का रहा तो जहां वह जाते थे वहां एक-दो मिनट तक योगा या अनुलोम-विलोम/कपालभाती इत्यादि के बारे में बताते थे। उसके बाद वह कालाधन के बारे में लोगों को तरह-तरह के आंकड़े बताना शुरू कर देते थे। आज तो सारी दालों और नूडल को बेचने का भी उन्होंने ठेका ले लिया है। आज दिल्ली सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है कि हर प्रोविज़नल स्टोर में पतंजलि में निर्मित सामान ही जाएगा। मैं ऐसी व्यवस्था की भी भर्त्सना करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आज इस सदन में बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर जो यह प्रस्ताव लाया है और आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने

02/12/2015/1300/**टी**0**सी**0/**ए**0**एस**0/2

2006और 2007 में एक बहुत अच्छी योजना लागू की थी जिसका फायदा प्रदेश के नागरिकों को मिल रहा है। महंगाई की मार से बचाने के लिए उस व्यवस्था को आगे भी लागू रखा जाये। सभापति महोदया आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति: धन्यवाद जगजीवन पाल जी। अब श्री राजेश धर्माणी (माननीय मुख्य संसदीय सचिव) चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव :माननीय सभापति महोदया जो प्रस्ताव आपने नियम-130 के अन्तर्गत सदन में प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। क्योंकि महंगाई का सीधा असर गरीब आदमी, आम आदमी के ऊपर पड़ता है। उसका फ़ायदा बड़े-बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों और बिचौलियों को होता है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं यदि वह सदन में मौजूद होते और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते ---

श्रीमती एन0एस0 ---जारी

02.12.2015/1305/NS/AS/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदी सचिव) द्वारा--- जारी

महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करते लेकिन शायद उनके पास इसके ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है और न ही उनके पास समय है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के जो माननीय सदस्य हैं यह बात उनकी ही नहीं है बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी समय नहीं है। आज लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनको इसकी चिन्ता करने की बजाए पूरी दुनिया में अपना अधिपत्य स्थापित करने, विश्व नेता बनने का जो उनका स्वपन है वह उसके प्रयास में लगे हुए हैं। हालांकि, इस प्रयास में जो हमारा सबसे नजदीकी मित्र देश नेपाल है ,आज उस देश की हमारे प्रति क्या नीति बन गई है उससे आप सब वाकिफ हैं। देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भूल गए हैं। अगर आज किसी देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे वहां पर पैकेज की घोषणा कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, उनके लिए भी पैकेज की घोषणा की जाती है। लेकिन पूरे हिन्दुस्तान के बारे में, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के बारे में और खास करके महंगाई की मार से बचाने के बारे में सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए। आपने यह ठीक कहा कि चुनाव के समय इन्होंने बड़े-बड़े वायदे किए और एक नारा लगाते थे कि "बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार" अब इस नारे को भी भूला दिया है और धीरे-धीरे इनका हल्कापन प्रदर्शित हो रहा है। महंगाई सिर्फ खाद्य पदार्थों को लेकर नहीं बढ़ी है बल्कि आम-आदमी की जरूरत की जो भी चीजें हैं वह भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद बढ़ी हैं। क्योंकि मोदी जी ने एक-एक प्रोडक्ट को नहीं पकड़ा, एक-एक आइटम का मूल्य बढ़ाने की बात सोची। इन्होंने सेवा कर को बढ़ाया उसके माध्यम से बिजली, पानी, यात्रा और हर चीज बढ़ गई हैं। पैट्रोलियम प्रोडक्ट कच्चे तेल का मूल्य अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में एक-तिहाई के लगभग पहुंच गया है। उसका फायदा लोगों को न देकर उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जिससे महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है। इनकी सोच उस दिन प्रदर्शित हुई जब दिल्ली की सरकार ने पहला बजट पेश किया। इसमें राहत अगर किसी को दी गई तो वह बड़े-बड़े कार्पोरेट हाऊसिज को दी गई। पांच प्रतिशत प्रति वर्ष कार्पोरेट टैक्स कम करने की बात कही गई है और पांच सालों में 25 प्रतिशत टैक्स कम होगा। साथ ही में दूसरी तरफ

02.12.2015/1305/NS/AS/2

उन चीजों का सर्विस टैक्स बढ़ा दिया जिसका आम आदमी पर असर पड़ता है। इसकी वजह से हर चीज बढ़ी है। आज हम केबल के माध्यम से जो टी.वी. चैनल देखते हैं या डायरैक्ट होम सर्विसिज का बिल देते हैं, मोबाईल और बिजली के बिल बढ़े हैं, हर चीज पर इसका असर पड़ा है। उस पैसे का भी सही प्रयोग अपने देश के विकास के लिए नहीं हो रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। जहां तक खाद्य पदार्थों की बात है क्योंकि इसका सीधा असर गरीब लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे-जैसे जिस आईटम का रेट बढ़ता है वे उनको खाना बंद कर देते हैं। प्याज के रेट बढ़े लोगों ने प्याज खाना बंद कर दिया। एक समय था जब प्याज छीलते हैं तो लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं और ऐसा अब भी होता है लेकिन अब प्याज खरीदते वक्त लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं और भाजपा सरकार के आने के बाद प्याज थाली से गायब हो गया इसलिए भी आंखो से आंसू निकलना शुरू हो गए। गरीब आदमी अगर दाल नहीं खाएगा तो उसका असर सीधा सेहत के ऊपर पड़ेगा। ऐसा ही हाल बाकि आईटम्ज़ को लेकर है। यहां कुछ आईटम्ज़ तो ऐसी हैं जिनके रेट सौ-सौ गुणा बढ़े हैं। जैसे छोटी इलायची का रेट लगभग दो हज़ार रूपये प्रति किलो हो गया है। वही हाल दवाईयों का है जैसे लाईफ सेविंग ड्रग्ज़ हैं जहां तक कि कैंसर और कई गम्भीर किस्म की बीमारियां हैं उनके ईलाज के लिए दवाईयां लोगों के उपयोग के लिए चाहिए उनको खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही एक तरफ तो महंगाई बढ़ी है और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी भी कम हुई है। आप सब जानते हैं कि मनरेगा का डेढ़ साल में क्या हाल हुआ है। कभी पैसा समय पर नहीं मिलता, कभी काम नहीं मिलता। अगर काम मिल गया तो पेमैंट समय पर नहीं होती।

श्री नेगी द्वारा जारी।

02.12.2015/1310/negi/AS/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव) जारी...
कई बार ऐसा संशय क्रिएट कर दिया जाता है कि इस योजना को लागू रखेंगे भी या नहीं रखेंगे। केन्द्र में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उसने गरीब लोगों के इलाज़ के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई थी । लेकिन आज इसके माध्यम से भी

लोगों का इलाज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने उस योजना का भी भट्ठा बिठा दिया है । इसी तरीके से जितनी हमारी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं थी उनकी भी हालत यही है। क्योंकि इम्प्लीमैन्ट करने वाले जो सैंक्शनिंग अथोरिटीज़ हैं उनको अभी तक ग्रीन सिग्नल नही मिल रहा है । यह ठीक कहा कि आज बड़े-बड़े घरानों की चिन्ता हो रही है । अम्बानी और अदानी की बात यहां पर हुई । इसका सीधा असर आप देख सकते हैं कि जब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय रिलाइंस के पैट्रोल पम्प बन्द थे और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की एन.डी.ए. की सरकार आई तो वे पम्प चलने शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर सबसिडी खत्म कर दी। जबकि हमारी सरकार की नीतियां यह थी कि जो पब्लिक सेक्टर कम्पनीज हैं उनके माध्यम से कन्जयूमर को बैनिफिट देने के लिए सबसिडी दी जाती थी । लेकिन आज उस सबसिडी को खत्म करने के लिए इसको धीरे-धीरे कम कर रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर्ज़ उसमें ज्यादा बैनिफिट उठा रहे हैं।

जहां तक दालों की बात है, दालों के रेट सचमुच में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इसमें पीछे बैंक ऑफ बडौदा का स्कैम सामने आया जिसमें हजारों करोड़ रूपये का लेनदेन हुआ और फेक कम्पनी बना करके यह किया गया । हालैंड से दालें खरीदने की बात की गई जबकि हालैंड अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भी दालें इम्पोर्ट करता है । यह भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने की बात करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार इनके समय में उल्टा बढ़ रहा है । जो बड़े-बड़े दलाल हैं और बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वे फायदा उठा रहे हैं। जब दालों के बारे में मीडिया में बहुत ज्यादा शोर हुआ तो उन्होंने एक मीटिंग वहां पर रख दी । उस मीटिंग का एक टी.वी. चैनल पर डिसकशन दिखा रहे थे और मैं बाईचांस उसको सुन रहा था, जो उसमें पार्टिसिपेन्ट था उन्होंने

02.12.2015/1310/negi/AS/2

प्वाइंट आउट किया कि जिनके साथ आप मीटिंग कर रहे हैं वे तो सबसे बड़े जमाखोर हैं। आपको इनके साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि इनके ऊपर आप कार्रवाई करो। उनके ऊपर कार्रवाई करके के बजाय आप उनसे चर्चा कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सोच गरीबों के हित में नही है बल्कि गरीबों को खत्म करने के बारे में यह सोचते हैं। गरीबों के लिए चाहे आवास की बात है, आज सीमेन्ट और सरिया के दाम बढ़े हैं। बाकी जो भी जरूरी चीज़ें हैं उनके रेट इनके आने के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। अगर कम हो रहा है जिससे देश को फायदा होगा तो

वह आज कृषि विकास दर कम हो रही है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट कम हुआ है । निर्यात कम हो रहा है जिससे हमें सीधा फायदा मिल सकता है और जिसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं। यह सबसिडी धीरे-धीरे खत्म करके गरीब लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बात हम सचमुच में एप्रिशिएट करना चाहेंगे कि हमारे हिमाचल सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी की जो पिछली टेन्योर था उस समय उसकी शुरूआत की थी कि यहां पर सस्ती दरों पर राशन दिया जाता है । यहां पर न सिर्फ सस्ती दरों पर राशन दिया जाता है बल्कि अगर हम हिन्दुस्तान की अन्य राज्यों के साथ तुलना करें तो यहां पर बिजली की दरें भी बहुत कम हैं। हमारे पानी की दरें बहुत कम हैं जिसका सीधा बैनिफिट लोगों को मिलता है । हमारे बाली जी, माननीय खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी से मैं एक आग्रह करूंगा,जैसा श्रीमती आशा कुमारी जी ने कहा कि यह धीरे-धीरे गैस सिलेन्डर पर से सबसिडी खत्म करना चाह रहे हैं । लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनकी कंजंप्शन बहुत कम है या जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह लगातार उसका प्रयोग कर सकें। वह अमरजैंसी में इसका प्रयोग करते हैं जैसे लकडियां सूखी न हो या कोई मेहमान आ गया तो उस समय गैस का प्रयोग करते हैं अन्यथा अपने घरेलू रूटीन कार्यों के लिए गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। स्वभाविक है कि उनकी गैस की कंजंप्शन कम होगी । लेकिन एक फैसल ऑयल कम्पनीज, हिन्दुस्तान की सरकार ने यह लिया है कि अगर किसी ने 6 महीने तक सिलेन्डर दोबारा रिफिल नहीं करवाया तो उसके कनैक्शन को सस्पैंड कर

02.12.2015/1310/negi/AS/3

दिया जाएगा। फिर उसको दोबारा से रिन्यु करवाना पड़ता है । रिन्यु करवाने के लिए फिर उन बेचारों को धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस रिन्युअल के झंझट को खत्म कर दें क्योंकि लोगों को बार-बार गैस एजैंसी में जाना पड़ता है और बार-बार उनको डॉकुमेन्ट्स सब्मिट करवाने पड़ते हैं। जो अति गरीब हैं, जो पुअरेस्ट एमंग पुअर हैं , इससे उनको ज्यादा इफैक्ट पड़ता है । जो लोग 6 महीने में सिलेन्डर को रिफिल नहीं कराते हैं उनको अपने कनैक्शन की रिन्युअल करानी पड़ती है और जब ....

श्री शर्मा जी द्वारा जारी ....

02.12.2015/1315/SLS-AS-1

श्री राजेश धर्माणी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव...जारी

उनको 6 महीने के अंदर अपने कनैक्शन की रिनिवल करवानी पड़ती है। अगर वह रिनिवल के लिए जाते हैं तो जो दिहाड़ीदार है, उसको अपनी दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है और कागज़ भी दोबारा से सब्मिट करने पड़ते हैं। इसलिए यह रिनिवल का झंझट खत्म कर दिया जाए। वह गरीब लोग हैं और इससे उनको नुकसान हो रहा है। उनकी गैस की ज़रूरत कम है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना सारा रसोई का काम गैस से ही कर सकें। इसलिए वह गैस का कम इस्तेमाल करते हैं।

सभापति महोदय, जो महंगाई बढ़ी है, इसका समाज के वनरेबल ग्रुप्स पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की सेहत के ऊपर इसका असर पड़ता है। इससे उस इनडिविजुअल का तो नुकसान होता ही है लेकिन अगर उसकी सेहत खराब होती है, तो समाज और देश का भी नुकसान होता है। एक तरफ हम डैमोग्राफिक डिविडैंड की बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर नौजवानों की संख्या बढ़ रही है जिससे हमारे देश की नैट प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसका लाभ हमारे देश को मिलेगा। लेकिन जो हमारे नौजवान साथी हैं, भाई-बहनें हैं, अगर उनकी सेहत ही ठीक नहीं होगी, अगर वह स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि वह देश के ज्यादा काम आ पाएंगे क्योंकि महंगाई का सीधा असर उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ रहा है। इसलिए जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हम उनसे पुरज़ोर मांग करते हैं कि महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई को घटाने के लिए आप कदम उठाएं, अन्यथा जो हाल आपका बिहार के लोगों ने किया है, वही हाल आपका बाकी जगह पर भी होगा; लोग आपको सबक सिखाएंगे।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

02.12.2015/1315/SLS-AS-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश कालिया: आदरणीय सभापति महोदय, आपने जो प्रस्ताव यहां पर नियम-130 के तहत महंगाई के ऊपर लाया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। जो हमारे विपक्ष के साथी हैं वह पहले तो कहते फिरते थे कि हम चर्चा से भागते नहीं हैं लेकिन आज जब यहां महंगाई के ऊपर चर्चा हो रही है तो आज वह हमारे साथी रैली का बहाना लेकर यहां से चले गए हैं। अच्छा होता वह बैठते और हमारी बातें सुनते। देश के प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ने जो वायदे किए थे, उनकी चर्चा आज हमारे सदस्यों ने की है और विपक्ष के लोग भी यहां आज उन बातों को सुनते। आज देश में दालों का क्या प्राईस है? जब दाल 40 रुपये किलो थी तब यह कहते थे कि महंगाई डायन है। आज दाल 200 रुपये किलो हो गई है तो महंगाई उनको डायन नहीं लगती बल्कि विकास लगता है।

दालों और सब्जियों की कीमतों का डायरैक्ट लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है , बिचौलियों को इसका लाभ मिल रहा है। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है ,इसलिए यह लालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी जी जब प्रधान मंत्री नहीं बने थे तब वह कहते थे कि आप मुझे देश का चौकीदार बनाओ ,मैं दिल्ली में बैठकर देश की चौकीदारी करूंगा। आज वह चौकीदार दुनिया के 39 देशों की यात्रा कर चुका है। केवल सिडनी में उनके जाने का ,उनकी कारों और होटलों का खर्चा लगभग 3.00 करोड़ रुपये आया है। हमने ऐसा चौकीदार अपना प्रधानमंत्री चुना है।

जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो भाजपा की कुछ नेत्रियां शिमला के चौड़ा मैदान में रैली कर रही थीं। मेरा कमरा वहां विधान सभा के साथ ही है। वहां पर कुछ भाजपा नेता खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार के विरोध में गृहणियां आई हुई हैं। भाजपा की नेत्रियां साथ में चकले, बेलने और पतीले जैसा सारा सामान लेकर आईं थीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज वह भाजपा की नेत्रियां कहां हैं जो उस समय इतने बर्तन लेकर आईं थीं? मैं आज बाहर बैठकर पेपर देख रहा था। आज गैस सिलेंडर का रेट 61/- रुपये बढ़

02.12.2015/1315/SLS-AS-3

गया है। जब हमारा समय था और चुनाव हुए ,तब इनके नेता घर-घर पर्चियां लेकर घूमें कि महंगाई बहुत ज्यादा है ,देश में जीना मुश्किल हो गया है, प्रदेश के बुरे हालात हैं। जिन मुद्दों के ऊपर यह सत्ता में आए थे ,उन्हीं मुद्दों के विरुद्ध आज ये काम कर रहे हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने यह परंपरा शुरू की कि हमारे यहां पर सब्सिडाईज्ड दालें दी जाएंगी। ऊना से इन्होंने इसकी शुरुआत की। उस समय मैं जिला कांग्रेस का प्रेजीडैंट और फर्स्ट टाईम एम.एल.ए. था। इन्होंने इस योजना के अंतर्गत दो दालें और एक लीटर तेल देना शुरू किया।

जारी ..गर्ग जी

02/12/2015/1320/RG/AG/1

श्री राकेश कालिया-----क्रमागत

और आज सबको यहां तक की जो मेरे जैसे इनकम टैक्सपेयर हैं ,उनको भी ये दालें सस्ते मूल्य पर दी जाती हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इनकी इस दूरदर्शी सोच से आज भी हिमाचल प्रदेश महंगाई की मार में उतना नहीं आया जितना आज के समय में आया है। आज महंगाई के कारण लोगों का जीवनयापन मुश्किल हो गया है। चाहे आप किसी भी चीज की बात कर लें, हर चीज की महंगाई बढ़ी है। जैसे श्री धर्माणी कह रहे थे कि अब तो सर्विस टैक्स भी बढ़ा दिया है। जिससे हर चीज का मूल्य और भी बढ़ गया है। अभी बिहार में विधान सभा के जो चुनाव हुए वहां भी महंगाई के कारण लोगों ने दिखा दिया है कि मोदी जी ने जो बातें की थीं वे सारी असत्य थीं। इसलिए काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ेगी। वहां मोदी ने सारी घोषणाएं चुनावों से पहले कर दीं ,वहां रैलियों में जाकर मोदी साहब ने पूछा कि कितना पैकेज बिहार को दूं, 50 हजार करोड़ दूं, 60 हजार करोड़ दूं, 70 हजार करोड़ दूं ,फिर सवा लाख करोड़ रुपये का पैकेज बिहार को दिया। अब वे यह पैकेज बिहार को देते हैं या नहीं देते, यह अलग बात है। लेकिन इन्होंने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बनाया और हमारा हिस्सा काट दिया है, लेकिन अब दुबारा से इनको यह पता चला है कि हमने जो गलत नीतियां बनाई हैं उनके कारण हमें इतनी मार पड़ी है। मध्य प्रदेश में भी हारे हैं और भी कई जगह चुनाव हो रहे हैं ,गुजरात में भी चुनाव हो रहे हैं ,

वहां चुनाव परिणामों की गणना हो रही है, लगता है कि वहां भी ऐसे ही कुछ नतीजे आएंगे।

सभापति महोदया, आपने मुझे यहां बोलने के लिए समय दिया, मैं इतना ही महंगाई के ऊपर बोलना चाहता था। आपका धन्यवाद।

समाप्त

2/-

02/12/2015/1320/RG/AG/2

सभापति : अब श्री किशोरी लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : आदरणीय सभापति महोदया, आपके द्वारा नियम-130 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव चर्चा हेतु यहां रखा गया है कि 'बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे।' यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जन-जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब-जब देश में गैर-कांग्रेसी सरकारें आई हैं तब-तब महंगाई बढ़ी है। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उसके पश्चात आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सारा मीडिया खरीदा हुआ था। चुनावों से पहले जब हम टी.वी. ऑन करते थे, तो हर चैनल पर मोदी साहब क्या कहते थे कि 'बहुत हुई महंगाई की मार ,अबकी बार मोदी सरकार।' तरह-तरह के वायदे उन्होंने लोगों से किए। लेकिन सत्ता में आने के बाद वे सारे वायदे भूल गए और देश में आज जो स्थिति महंगाई से बनी हुई है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो गरीब लोग गांवों में रहते हैं, अधिकतर लोग कांग्रेस के वोटर हैं। मोदी साहब सोचते हैं कि इनको ही खत्म कर दो ताकि हम देश के परमानेंट स्वयंभू हो जाएं। इसलिए यह एक बहुत बड़ा अहम् मुद्दा है। इस पर जनता को विचार करना होगा कि आपने खत्म होना है या इन लोगों को खत्म करना है। जिन्होंने सोने का मृग बनकर जनता का मोह मोह लिया ,वोट लिए और तरह-तरह के झूठे वायदे लोगों से किए थे। नौजवानों से वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे ,लेकिन जितने भी वायदे इन्होंने किए उन पर केन्द्र की सरकार खरी नहीं उतरी है। आज महंगाई की मार से सारा देश त्राही-त्राही कर रहा है और महंगाई की मार से त्रस्त है जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। आज देश के लोग इस सरकार की ओर देख रहे हैं। केवल खाद्य पदार्थों पर ही महंगाई नहीं बढ़ी ,सभी चीजों में उछाल आया है। जितनी भी हमारी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं सभी पर महंगाई बढ़ी है। इस लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्रस्त है।-----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

02/12/2015/1325/MS/AG/1

श्री किशोरी लाल जारी----------

जितनी भी हमारी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं सभी की कीमतें बढ़ी हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई से जनता त्रस्त हैं। जो दाल गरीब लोग 40-/रुपये प्रति किलोग्राम की खाते थे उसकी कीमत आज 220-/रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आज खाने के तेल की कीमत 150-/रुपये है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं इन सबकी कीमतें भी बढ़ रही हैं लेकिन इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान केवल झूठे वायदे करने पर है। मुझे हैरानी होती है कि गेहूं किसान पैदा कर रहा है लेकिन आटा कौन बेच रहा है? वह आटा एक बड़ी कम्पनी 'पतांजलि' बेच रही है। हिन्दुस्तान में बाबे की कम्पनी यह काम कर रही है। बाबे तो भगवान का भजन करने के लिए होते हैं लेकिन वे व्यापारी बन गए हैं। उनके आटे की कीमत 29-/ रुपये प्रति किलोग्राम है और 10किलो की आटे की थैली 290-/रुपये में बिक रही है। इसमें ऐसा कौन सा मंत्र मिला दिया कि आटा इतना महंगा बिक रहा है? मुझे लगता है कि वे बाबे नहीं बल्कि देश को लूटने आए हैं। वे यहां लूट-खसूट कर रहे हैं। वह बाबा कुवांरे हैं परन्तु यदि उनका परिवार होता तब तो मेरे ख्याल से सारे हिन्दुस्तान को लूट ही लेते। मुझे समझ में नहीं आता कि उनको कितनी भूख है? इस पैसे को वे कहां डालेंगे? यदि अकेले व्यक्ति का यह हाल है जो सारे हिन्दुस्तान को लूट रहा है तो बाकी सन्यासियों का क्या हाल होगा, यह सोचने वाली चीज है। मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल के आदरणीय मुख्य मंत्री जी को कि वर्ष 2007 में उन्होंने सरकारी डिपुओं के माध्यम से दालें, तेल, नमक और आटा इत्यादि लोगों को सस्ता दिया है। इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को राहत मिली है और इस राहत से लोगों पर महंगाई का कोई असर नहीं हुआ है। अगर महंगाई का असर है भी तो दूसरी चीजें के ऊपर है। जो डिपुओं के माध्यम से सरकार जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है उसके लिए हिमाचल सरकार बधाई की पात्र है। मुझे लगता है कि देश की जनता शीघ्र ही इसका निर्णय लेगी। जब देश से मोदी सरकार जाएगी तभी महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। सभापति महोदया, आपने मुझे यहां बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय हिमाचल। जय बाबा बैजनाथ ।

(Concluded)

02/12/2015/1325/MS/AG/2

सभापति (**श्रीमती आशा कुमारी**): किशोरी लाल जी धन्यवाद। आज की चर्चा के आखिरी वक्ता माननीय सदस्य श्री बम्बर ठाकुर जी हैं। अब चर्चा में बम्बर ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री बम्बर ठाकुर: सभापति महोदया, आज नियम 130 के तहत महंगाई के ऊपर जो ये अति महत्वपूर्ण विषय यहां पर चर्चा हेतु रखा गया है, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, इस विषय पर काफी समय से चर्चा हो रही है। जब यह चर्चा शुरू होनी थी उसके चन्द मिनट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां से भागकर चले गए। वास्तव में उनके पास कोई बहाना भी सोलिड नहीं था। जो आपने महत्वपूर्ण विषय यहां पर रखा है उस विषय पर वे न डिफैंस कर सकते थे और न ही बोल सकते थे इसलिए उनको भागना पड़ा। सभापति जी, आज पूरा देश महंगाई की चपेट में है और पूरे देश में जो इन्होंने वोट मांगे थे और जैसा अभी आपने कहा कि अच्छे दिनों की शुरूआत होगी, उस नाम पर इन्होंने वोट मांगे और पूरे देश के किसानों, मज़दूरों, युवाओं और गरीबों को ठगा और ठगकर अपनी कुर्सी पर काबिज़ हो गए। आज विपक्ष को और धूमल साहब को,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

/1330/02.12.2015**जेके /एजी**/ 1

श्री बम्बर ठाकुर:-------**जारी**--------
आज विपक्ष को और धूमल साहब को इसका कोई ज़वाब नज़र नहीं आ रहा था इसलिए वे यहां से भाग गए। अभी बाहर रैली रखी हुई है। मैं यहां सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस रैली में आप हिमाचल प्रदेश के किसानों को बताएं, हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताएं कि किन मुद्दों के ऊपर आप लोगों ने हिन्दुस्तान में चुनाव लड़ा था? आज रैली आप किसलिए कर रहे हैं? आज देश के अन्दर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि

किसान रोटी कैसे खाएगा? आज गरीब कैसे रोटी खाएगा? आज किसान का बच्चा जो ट्रेनिंग करने के लिए स्कूलों व कॉलेजिज में जा रहा है वह वहां पर ट्रेनिंग कैसे करेगा? वहां पर उसके माता-पिता कैसे-कैसे अपने बच्चों को भेजते हैं? किस प्रकार से वहां पर वह अपने बच्चों को रोजी-रोटी का इन्तजाम करता होगा? कैसे वह डॉक्टर बनेगा और कैसे वह इंजीनियर बनेगा? गरीब अपने बच्चे को प्लम्बर, फीटर और इलैक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग कैसे करवाएगा? उसके पास कहां से रोटी के लिए पैसा आएगा? आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रैली के अन्दर इस बात का ज़वाब देना चाहिए। वे सदन के अन्दर तो इस बात को फेस नहीं कर सके। आज उनको रैली में इस बात को कहना चाहिए क्योंकि जे0पी0 नड्डा जी भी दिल्ली से उस रैली में आए हैं और इनके प्रभारी आए हैं। केवलमात्र श्री वीरभद्र सिंह जी के ऊपर बात करने से बात नहीं बनेगी। श्री वीरभद्र सिंह के ऊपर केस करने से आप लोगों के ख्याली पुलाव पूरे नहीं होंगे। आप सरकार नहीं बना सकते हैं। आज आप लोगों को देश की जनता को, प्रदेश की जनता को यह बताना होगा कि आप लोगों ने जिस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा था उस मुद्दे का क्या हुआ? वह अच्छे दिन कहां गए? अरहर की दाल 250 रूपये तक पहुंच गई। मेरी उम्र 46 वर्ष हो गई और माननीय सभापति महोदया इन 46 वर्षों में मैंने पहली बार देखा कि दालों की कीमतें 100 रूपये से ऊपर चली गई। कभी 80 रूपये से ऊपर दालों की कीमतें नहीं जाती थी। 250रूपये तक दालों की कीमतें चली गई। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गुजरात से मोदी जी आते थे और हिमाचल प्रदेश के अन्दर जनसभा करते थे। दूसरे दिन उनको जम्मू जाना होता था। आप रिकॉर्ड उठा करके देख

/1330/02.12.2015**जेके /एजी**/ 2

लीजिए। मैं धूमल साहब और नड्डा साहब से कहना चाहूंगा कि जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में उन्होंने जनसभा की तो फिर वे कांगड़ा से सीधे गुजरात चले गए। गुजरात से फिर जम्मू आए। वह पैसा कहां से आता था? वे रात को यहां पर रुक सकते थे और यहां से जम्मू जा सकते थे लेकिर हर रोज़ चाहे मुम्बई में जनसभा हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे बंगलौर में हो उनको जो अदानी के द्वारा दिया गया जहाज था वह सीधा गुजरात से आता था और फिर हिमाचल आत था। हिमाचल से फिर गुजरात जाता था और फिर मुम्बई जाता था। फिर मुम्बई से गुजरात आता था। यह जो पैसा करोड़ों , खरबों रूपया उन धन्ना सेठों से लिया आज उनको फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, मोदी साहब हिन्दुस्तान के गरीबों के के सीने के ऊपर चक्की चला

रहे हैं। आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जिस मजदूर की ये बात करते थे ,किसान हितैषी होने की बात करते थे और गरीब हितैषी होने की बात करते थे। मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूं। चाय बेच कर मैं प्रधानमंत्री बना। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस सदन के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब आप चाय बेचते थे तब तो आपको मालूम है कि कैसे किसान गेहूं पैदा करता है, कैसे मक्की पैदा करता है और कैसे चावल पैदा करता है? उसको तो उसका दाम पूरा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो जमाखोर हैं उनको आपने इज़ाजत दे दी है। आज वे लोग करोड़ों, अरबों रूपये कमा रहे हैं। जितना पैसा मोदी साहब के जहाजों के ऊपर लगाया गया। इलैक्शनों के होर्डिंग्ज के ऊपर लगाया गया उससे कई हजार गुणा पैसा इकट्ठा करने की छूट उनको दे दी गई है। आज यदि रैली करनी है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूंगा कि इस बात का ज़वाब हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है। इस बात का ज़वाब हिन्दुस्तान की जनता चाहती है। क्या आपके पास इन बातों को कहने के लिए रैली में कोई मुद्दा है? केवलमात्र हिमाचल प्रदेश के अन्दर ध्यान बांटने के लिए ताकि लोग मंहगाई की हाहाकार न करें। रैलियां न करें, जलसे न करें। केवलमात्र एक षड़यंत्र के तहत श्री वीरभद्र सिंह जी के ऊपर बार-बार ऊंगली उठाते हैं। मुकद्दमें कर रहे हैं। उनको भी

/1330/02.12.2015**जेके /एजी**/ 3

मालूम है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन लोगों का ध्यान बंटाओ। लोगों का ध्यान बांटो ताकि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न हो जाएं। ऐसे ड्रामें करके और ऐसे षड़यंत्र करके हम सत्ता की दहलीज़ में पहुंच सके, इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

02.12.2015/1335/SS-AG/1

श्री बम्बर ठाकुर क्रमागत:
हम सत्ता की दहलीज़ तक पहुंच सकें इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के हथकंडे अपना करके उनके मनसूबे पूरे नहीं होंगे। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मोदी जी से पूछना चाहूंगा कि आप चाय की बात करते हैं

कि आप चाय बेच करके प्रधान मंत्री बने। आपको मालूम है कि एक मजदूर सड़क पर काम करता है, 250 या 300 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी लेता है और शाम को उसी दिहाड़ी से अपने बच्चों, पत्नी को पालेगा। उसी में अपने रिश्तेदारों को भी देखेगा। अपनी गमी और खुशी को भी देखेगा। उसे सिर्फ 300 रुपये दिहाड़ी है और आपने एक दाल 250 रुपये प्रतिकिलो कर दी है तो वह कैसे अपने मकान को बनायेगा? वह कैसे अपने परिवार का खर्चा करेगा? कैसे अपना जीवन-यापन करेगा? क्या मोदी साहब आपने इस बात के बारे में भी सोचा है? मैं माननीय मुख्य मंत्री, राजा साहब आपका और आपकी दूरदर्शी सोच का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपको बहुत तर्जुबा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने देखा कि मोदी साहब ने दिल्ली के अंदर इतनी महंगाई कर दी, गरीब अपना मकान नहीं बना सकता, गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता तो आपने मजदूरों के लिए प्रदेश के अंदर योजनाएं चलाईं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने श्रमिक बोर्ड बनाया जहां से आज हमारे श्रमिकों को उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मिलता है। हमारे जो किसान लोग हैं या मजदूर हैं यदि कोई उनके घर में बीमार हो जाता है तो भी उनको उसमें से बीमारी का खर्चा मिल रहा है। मकान बनाने के लिए भी राहत मिल रही है। आपने श्रमिक बोर्ड नहीं बनाया होता तो ये मजदूरों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते। इसलिए मुख्य मंत्री महोदय मैं आपको और आपकी कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार की योजनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाई हैं। यदि ये योजनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं होतीं तो ये मजदूरों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते। यदि आपने स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान नहीं किया होता तो गरीब बच्चे कैसे स्कूल जाते? केन्द्र सरकार ने हर चीज़ इतनी महंगी कर दी कि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। राजा साहब मैं आपकी सोच का धन्यवादी हूं, उसके

लिए आपको मुबारकवाद देनी पड़ेगी कि आपने देखा कि दिल्ली के अंदर मोदी सरकार ने इस प्रकार के गलत फैसले ले लिये हैं तो आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर एच0आर0टी0सी0 की बसों में बच्चों को आने-जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान कर दी ताकि हमारा हर नागरिक शिक्षित हो। वह शिक्षा ग्रहण करे। आपने जगह-जगह स्कूल भी खोल दिए और बच्चों को आने-जाने की सुविधा भी प्रदान कर दी परन्तु यदि मोदी साहब की चले तो न तो बच्चे पढ़ सकते हैं और न ही किसान आगे बढ़ सकता है। न ही

मजदूर आगे बढ़ सकता है और न ही कोई नौजवान आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन से भाग कर गए हैं उन तक यह आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप में ज़रा-सी भी नैतिकता है तो आज इस रैली के माध्यम से दिल्ली में प्रधान मंत्री जी से कहिये कि आपको सरकार चलानी नहीं आती है आप रिजाईन करिये। हिन्दुस्तान के अंदर आपने हाहाकार मचा दी है। हर किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान आज त्राहि-त्राहि कर रहा है उसके लिए आपको रिजाईन करने की ज़रूरत है। ऐसी रैलियां करके, ध्यान बांटकर और वीरभद्र सिंह जी पर आक्षेप करके आप अपने मनसूबों को पूरा नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदया, आज जो आपने महंगाई के ऊपर अति महत्वपूर्ण विषय रखा है और उस पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। जय हिन्द, जय हिमाचल।

समाप्त

02.12.2015/1335/SS-AG/3

सभापति: चर्चा समाप्त। अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री: सभापति महोदया, आपके द्वारा अति महत्वपूर्ण, संवेदनशील और आज के सन्दर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विषय नियम-130 के अन्तर्गत उठाया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आपके अतिरक्त सात अन्य हमारे साथियों ने इस चर्चा में विस्तार से अपना मत रखा। अपनी बात रखी और एक-एक करके जो इश्यु उन्होंने उठाये हैं उसको मैं बाद में लूंगा।

जारी श्रीमती के0एस0

02/1340/12.2015.**केएस/एजी**/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी----
एक-एक करके जो इश्यू इन्होंने उठाए हैं, उनको बाद में लूंगा। । जो प्रस्ताव आपने दिया पहले मैं उसका विस्तृत जवाब देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया ,बढ़ती मंहगाई का मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण, संवेदनशील एवं एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। सरकार व विभाग द्वारा इस पर अंकुश लगाने हेतु भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि हि0प्र0 में अधिकतर वस्तुओं, खास तौर पर खाद्य वस्तुओं का उत्पादन मांग से काफी कम है। फलस्वरूप हम प्रदेश के बाहर पड़ौसी राज्यों पर निर्भर है। स्त्रोत बाजारों में हुई मूल्य वृद्धि पर राज्य सरकार का नियन्त्रण नहीं रहता है। यदि स्त्रोत बाजारों में वस्तुओं के भावों में उतार-चढ़ाव आता है तो उसका असर निःसंदेह इस राज्य पर पड़ना स्वाभाविक है। गत वर्ष के दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण व समय पर उचित कदम न उठाने के कारण हुई है।

सभापति महोदया, यदि इस वक्त हमारे विपक्ष के साथी यहां होते तो बड़ा अच्छा होता वे अपने सुझाव भी देते और केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में भी अपना पक्ष रखते।

यह सत्य है कि जबसे केन्द्र में नई सरकार सत्तासीन हुई है, सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसका कारण केन्द्र सरकार द्वारा समय पर आवश्यक वस्तुओं का आयात व वितरण न करना है। यह जानते हुए भी कि दालों का उत्पादन इस वर्ष लगभग 30 लाख टन कम हुआ है।

इसका ज्ञान था क्योंकि इस बारे में कई मीटिंग्ज़ गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों की हुई थी।

02/1340/12.2015.**केएस/एजी**/2

केन्द्र सरकार ने समय रहते दालों का आयात करने बारे आवश्यक कदम नहीं उठाए और ऐसी अन्य कई वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन तो पर्याप्त हैं परन्तु उनके भण्डारण व वितरण की उचित व्यवस्था नहीं की गई। यदि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के पिछले एक साल की कीमतों की तुलना की जाए तो स्पष्ट होता है कि खाद्य वस्तुएं आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हो चुकी है। यह नीचे दी गई औसतन भाव की सूची के आकलन से स्पष्ट हो जाता है:

क्रम संख्या	वस्तु	नवम्बर, 2014	नवम्बर,2015	बढ़ौत्तरी प्रतिशतता
1	दाल चना	44.00	72.00	64
2	अरहर दाल	82.00	158.00	93
3	दाल उड़द	74.00	143.00	93
4	काला चना	45.00	71.00	58
5	दाल मलका	80.00	93.00	16
6	सरसों तेल	101.00	128.00	27
7	प्याज	25.00	35.00	40
8	बन्दगोभी	17.00	26.00	53
9	टमाटर	24.00	50.00	108
10	मटर	45.00	75.00	67

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मूल्यवृद्धि इतनी हुई है कि आम आदमी को रोज़मर्रा की वस्तुओं का प्रबन्ध करना मुश्किल हो गया है और उस पर बहुत अधिक अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

जहां तक सब्जियों की कीमतों में वृद्धि का प्रश्न है इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान प्याज, आलू इत्यादि की कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई है जिस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा 385 सब्जी विक्रेताओं

02/1340/12.2015.**केएस/एजी**/3

के निरीक्षण किए गए जिनके तहत विभाग द्वारा 86 मामलों में कार्यवाही करते हुए 15.08 क्विंटल प्याज जब्त किया गया है। विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान में सब्जियों (प्याज, आलू इत्यादि) के दामों में काफी कमी आई है।

दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा हि0प्र0 व्यापारिक वस्तुएं (अनुज्ञप्ति एवं नियन्त्रण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत दालों की न्यूनतम भण्डारण सीमा 30 क्विंटल से घटाकर 20 क्विंटल की गई तथा हि0प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के अन्तर्गत सभी दालों की अधिकतम भण्डारण सीमा 100 क्विंटल निर्धारित की गई ताकि दालों की जमाखोरी पर अंकुश लगाकर इनकी कीमतों पर नियन्त्रण रखा जा सके। इसी दिशा में कार्य करते

हुए प्रदेश सरकार ने विभाग के माध्यम से व्यापारियों/दुकानदारों के निरीक्षण करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू कर इनकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित किया। सरकार द्वारा विशेष अभियान के तहत दिनांक 28.10.2015 से 05.11.2015 तक जमाखोरों एवं मुनाफाखोरों से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 1,322 छापे मारे गए तथा 118.37 क्विंटल दालें जब्त की गई है, जिससे दालों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगा है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

2.12.2015/1345/av/as/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री क्रमागत------

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग यह सुनिश्चित करता है कि व्यापारी वर्ग उपभोक्ताओं से निर्धारित लाभांश की सीमा से अधिक लाभांश प्राप्त न करे। इस बारे प्रवर्तन वर्ग को नियमित रूप से निरीक्षण कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो निम्न प्रकार से है :-

.1 जिला नियंत्रक-25
.2 खाद्य आपूर्ति अधिकारी - 30
.3 निरीक्षक - 37

वर्ष 2015-16 में किए गए निरीक्षण कार्य व अन्य प्रर्वतन कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	विवरण	16-2015मास 10/2015 तक
.1	किए गए निरीक्षणों की संख्या	24,408
.2	पंजीकृत केस	01
.3	व्यक्ति जो गिरफ्तार किये गये	---
.4	व्यक्ति जिन्हें लिखित चेतावनी दी गई	532
.5	विभागीय कार्रवाई के अंतर्गत दोषी/दण्डित पाए गए व्यक्तियों की संख्या	1876
.6	अनियमितता के कारण जब्त की गई प्रतिभूति राशि	-/11,43,379रुपये
.7	जब्त किये गये माल की राशि	-/18,11,941रुपये

2.12.2015/1345/av/as/2

उपरोक्त के दृष्टिगत व खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों बारे प्रदेश सरकार अति संवेदनशील है। माननीय वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश की गरीब जनता को राहत पहुंचाने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :

.1 दालों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्टेट सबसिडी स्कीम के अधीन दी जाने वाली दालों पर अनुदान राशि को 50 प्रतिशत प्रति किलोग्राम बढ़ा दिया है। जब से रेट बढ़े हैं, हम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो सबसिडी देते थे उसमें हमने 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

.2 मैं यू.पी.ए. सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट (एन.एफ.एस.ए.) को अधिनियमित करने के लिए धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश एन.एफ.एस.ए. को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। हमारी यू.पी.ए. सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट बनाया उसको लागू करने वाली हमारी प्रदेश सरकार नम्बर दो पर आई है। एन.एफ.एस.ए. हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए काफी मददगार सिद्ध हुआ है तथा इसके लागू होने से प्रदेश की गरीब जनता को काफी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश बी.पी.एल. परिवारों को नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट (एन.एफ.एस.ए.) के प्रावधानों से बढ़कर खाद्यान्न प्रदान किए जा रहे है जिस पर अतिरिक्त व्यय प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो एन.एफ.एस.ए. में मिलता था उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमैंट ने उसको अपनी तरफ से ज्यादा सबसिडाइज्ड किया है।

.3 जनजातीय क्षेत्रों में नॉन-एन.एफ.एस.ए. परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

.4 नॉन-ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को चीनी 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।

2.12.2015/1345/av/as/3

इन सबसे पता चलता है कि यह सरकार कितनी संवेदनशील है। हमने गरीब लोगों को इनसुलेट किया है कि उन पर महंगाई का असर न पड़े। हिमाचल प्रदेश में श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण स्कीम के तहत हर चीज को सबसिडाईज कर रही है।

दालों की आसमान छूती कीमतों के बावजूद भी प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को जैसे यहां पर कालिया जी ने बात कही। चाहे कोई इनकम टैक्स पेई है, गवर्नमैंट इम्प्लॉईज हैं या यहां तक कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्ज हैं; उनको भी सस्ती दालें, सस्ता तेल, आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध करवा रही है जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 210 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदया, मैं यहां पर एक और उल्लेख करना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो जाते-जाते हमारे लिए सौ करोड़ रुपये की लायबिलिटी छोड़ गई। इनकी लायबिलिटी हमने आकर के पे की है। मैं कई बार हैरान होता हूं क्योंकि ये सवाल करते हैं मगर जवाब लेने से पहले यहां से भाग जाते हैं। इनकी रैली इनको ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई।

श्री वर्मा द्वारा जारी

02/12/2015/1350/**टी**0**सी**0/**ए**0**एस**0/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री --- जारी

कई बार हैरान होता हूं क्योंकि ये सवाल करते हैं मगर जवाब लेने से पहले यहां से भाग जाते हैं। इनकी रैली इनको ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन अपना पक्ष रखने के लिए इनको कुछ न कुछ लोगों को यहां छोड़ना चाहिए था। ताकि इनकी बात भी सुनते और उनका जवाब भी देते। राज्य सरकार द्वारा अनुदानित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम सं0	वस्तु	मूल्य	स्केल (मात्रा)
.1	काबली चना	40.00रू0 प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह
.2	दाल चना	40.00रू0 प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम तीन या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रतिमाह
.3	काला मसर	63.50रू0 प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम पांच या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रतिमाह

.4	खाद्य तेल	55.00रू0 प्रति किलोग्राम	एक लीटर एक या दो सदस्यों वाले परिवार को तथा 2 लीटर तीन या तीन से अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति माह।
.5	आयोडीन नमक	4.00रू0 प्रति किलोग्राम	एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह

इस प्रकार से हम हर चीज ह्व व ।/3 मूल्य पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आज के समय में जब खुले बाजार में दालें लगभग 125 रूपये से 200 रूपयें प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली उपरोक्त दालें 40 रूपये से 63.50 रूपये प्रति किलोग्राम तक की दर में प्राप्त होना एक बहुत बड़ी राहत है, जोकि सरकार आज के समय में सभी श्रेणियों के राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध

02/12/2015/1350/**टी**0**सी**0/**ए**0**एस**0/2

करवा रही है। माननीय सभापति महोदया आपने चर्चा में होर्डिंग के बारे में कहा। इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए मैंने आंकड़े पढ़े कि 24 हजार से ज्यादा हमने उसमें इन्सपैक्शन करवाई है और जहां-जहां कानून का उल्लंघन हुआ, वहां जुर्माना भी किया है। श्री कुलदीप कुमार जी ने ब्लैक मनी और पतंजलि की बात की, मैं अधिकारियों को कहूंगा कि देखें कि उसमें कितने परसेंट मार्जन है। मैक्सिमम प्राईस क्या लिखते है और डीलर्ज़ और डिस्ट्रिब्यूटर्ज़ को कितना मार्जन देते हैं और वे मंहगा कैसे बेचते हैं। पूरा कानून देखकर उसको चैक करेंगें।

महेश्वर सिंह जी ने कहा कि मोदी सरकार कुम्भकरण की नींद सो गई है। अभी महेश्वर सिंह जी यहां पर नहीं है वरन् कुम्भकरण की नींद से जगाने के लिए ये उनके पुराने साथी रहे हैं, ये ही अपनी कोई दवाई इनको दें, कोई बूटी दें ।

सभापति महोदया, माननीय जगजीवन पाल जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। अगर विपक्ष के माननीय सदस्य यहां होते तो एक कॉमन रैज्योल्यूशन बना कर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेजते कि इतनी मंहगाई हुई है और इससे इतना नुकसान हो रहा है। मगर क्योंकि गरीब आदमी के प्रति जब भी कोई चर्चा होती है, उसमें हिस्सा

नहीं लेना इनकी आदत बन गई है। कल हमारे साथी नीरज भारती जी इनके काम रोको प्रस्ताव के बारे में कह रहे थे । जब काम किया ही नहीं तो रोकना कब है?

सभापति महोदया ,राजेश धर्माणी जी ने गैस के ऊपर गरीब आदमी को राहत देने की एक महत्वपूर्ण बात की है, इन्होंने पहले भी इस बारे में मामला उठाया था और हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को इस बारे में लिखा है और हम उनके उत्तर का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगें क्योंकि यह सैंटर गवर्नमैंट से सम्बन्धित है।

हमारे सभी साथियों ने डीज़ल के बारे में कहा, क्योंकि ट्रांस्पोर्ट महकमा भी मेरे पास है, मैं कहना चाहूंगा कि डीज़ल के मूल्य में वर्ष 2013 और आज में कोई कमी

नहीं आई। एक-डेढ़ रुपये के करीब घटता-बढ़ता रहता है। कभी एक रुपया ज्यादा और कभी एक रुपया कम होता है और क्रूड ऑयल की कीमत 33-35 परसेंट रह गई है। तो यह रज्योल्यूशन डालकर गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं ताकि मंहगाई से हमें राहत मिल सके। ऐसे ही हमारे साथी राकेश कालिया जी ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, मैं अधिकारियों से कहूंगा कि इनके ऊपर भी गौर करें।

श्री किशोरी लाल जी व बम्बर ठाकुर जी ने भी इस सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सभापति महोदया, अन्त में--

श्रीमती एन.एस.द्वारा जारी---

खाद्य, **नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री** ------**जारी**

माननीय सभापति महोदया, अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा तथा हमारे अन्य साथियों ने जो मूल्य वृद्धि पर चिंता जताई है वह उचित प्रतीत होती है। मगर उसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां ही जिम्मेवार मानी जा सकती है। जबकि हमारी सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के मामले में सजग है। बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद हमने अनेक कदम उठाकर के उपभोक्ताओं को बाजारी कीमतों से इनसुलेट करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश सरकार महंगाई से राहत देने के

लिए वचनबद्ध है। मैं यहां पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार भी नवम्बर से लेकर मार्च तक जो हम राशन देंगे उसमें दालें 50 रुपये से कम रेट पर देंगे चाहे मोदी सरकार उसके रेट दो सौ रुपये कर दे या चार सौ रुपये कर दे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार राहत दिलाने के लिए वचनबद्ध है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि भविष्य में आवश्यक मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए हर सम्भव पग उठाए जाएं ताकि प्रदेश की गरीब जनता को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध हो सकें।

अंत में, मैं केंद्र की यू.पी.ए. सरकार का एन.एफ.एस.ए. लाने के लिए धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यहां पर यह सब्सिडी की स्कीम चलाई थी। जिसके कारण आज हम गरीब आदमी को महंगाई से इनसुलेट कर रहे हैं। मैं यह भी चाहूंगा कि सदन यह प्रस्ताव कर सकता है कि बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार कदम उठाए। तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों में गिरावट के मुद्दे पर देश में तेल के दाम भी उसी अनुपात में कम होने चाहिए। गैस की सब्सिडी जो रोज-रोज बढ़ रही है उसकी चिन्ता हमारे सभी सदस्यों ने व्यक्त की है। इसके लिए अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है।

सभापति (**श्रीमती आशा कुमारी**): माननीय मंत्री जी, कृपया आप एक मिनट बैठ जाइए। नियम-130 के तहत जो चर्चा थी वह आपके उत्तर के साथ समाप्त हो गई है। क्या आप सरकार की ओर से नियम 117 के तहत अलग से एक प्रस्ताव देना चाहेंगे?

02.12.2015/1355/NS/AS/2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : सभापति जी, मैंने यही कहा कि अगर चाहे तो पार्लियामैंट्री मिनिस्टर प्रस्ताव ला सकते हैं और उस प्रस्ताव के ऊपर यह सदन अपना मत दे सकता है। मैंने अपना जवाब पूरा करने के बाद यही सुझाव दिया कि हमारे जो सदन में 8-10 माननीय साथी बोलें उन सबकी यही राय थी कि अगर आज हमारे विपक्ष के साथी सदन में उपस्थित होते तो यह पूरा प्रस्ताव बनकर सहमति से चला जाता। वे आज नहीं है तो इसमें हमारी रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि कम-से-कम हमारे हाऊस की तरफ से एक प्रस्ताव गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया को चला जाए क्योंकि मुख्य रूप से महंगाई पर कंट्रोल करने की उन्हीं की जिम्मेवारी है।

सभापति महोदया, हमारी सरकार मूल्य वृद्धि के लिए हर सम्भव कदम उठायेगी। अगर आप इज़ाजत दें तो--------

श्री नेगी द्वारा ----जारी।

02.12.2015/1400/negi/AG/1

मा0 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ... जारी...
माननीय सभापति जी अगर आप इज़ाजत दें तो नियम-117 के तहत मैं दूसरा प्रस्ताव पढ़ देता हूं। अगर इज़ाजत मिलेगी तो उसके ऊपर वोटिंग करा सकते हैं।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): आमतौर पर सदन में जो नियम-117 के तहत नोटिस आता है उसके लिए पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है । मगर हाऊस सुप्रीम है। अगर हाऊस की अनुमति है, माननीय मंत्री जी को यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अगर हाऊस एक मत है तो स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । क्या हाऊस इसके लिए सहमत है?

सदस्यगण: जी हां।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): माननीय मंत्री जी आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय सभापति महोदया,यह "सदन प्रस्ताव करता है कि बढ़ती महंगाई को खासतौर पर दालों व खाने की वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार कदम उठाए। सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि तेल खासतौर पर पैट्रोल, डीज़ल व गैस की अन्तर्राष्ट्रीय दामों में गिरावट के मद्देनज़र देश में तेल के दाम भी उसी अनुपात में गिराए जाएं जिस अनुपात में क्रूड व बाकी पैट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम कम हों"।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि बढ़ती मंहगाई को खासतौर पर दालों व खाने की वस्तुओं के दामों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार कदम उठाए। सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि तेल के खासतौर पर पैट्रोल, डीज़ल एवं गैस के अन्तर्राष्ट्रीय दामों में गिरावट के मद्देनज़र देश

में तेल के दाम भी उसी अनुपात में गिराए जाएं जिस अनुपात में क्रूड व बाकी पैट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम कम हों। "

प्रस्ताव पारित

02.12.2015/1400/negi/AG/2

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 3 दिसम्बर, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है ।

धर्मशाला- 176215 **सुन्दर सिंह वर्मा**,
दिनांक: 2 **दिसम्बर**, 2015 **सचिव।**

*****